राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

@swatantraprabhatmedia | @swatantramedia | RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) | @SwatantraPrabhatonline | news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, शुक्रवार, 06 फरवरी 2026
वर्ष 14, अंक 287, पृष्ट 04, मूल्य: 01 रुपया
www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

बारिश में भीगी इंसानियत, चालान में उलझी व्यवस्था..03

क्लोन ऐप से करोड़ों की ठगी, बड़ा नेटवर्क का खुलासा..04

नरवणे की बुक पर बवाल! मनमोहन सरकार के वक्त पूर्व जनरल ने रॉ पर लिखी किताब, 19 साल से लड़ रहे केस

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' को लेकर संसद में उठे तूफान के बीच एक पुराना मामला फिर सुर्खियों में आ गया है. यह मामला मेजर जनरल (रिटायर) वीके सिंह का है, जिनकी 2007 में प्रकाशित किताब 'इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंसः सीक्रेट्स ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग' है. किताब प्रकाशित होने के 19 साल बाद भी उन पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट (OS) के तहत मुकदमा चल रहा है. मामले की अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है।

दरअसल, बीते दिनों सरकार ने संसद में दावा किया कि राहुल गांधी लोकसभा में नरवणे की अप्रकाशित किताब से अंश नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है. लेकिन सरकार ने यह नहीं बताया कि रक्षा मंत्रालय की अपनी प्रशासनिक शाखा ने किताब को एक साल से अधिक समय से रिव्यू के तहत रखा हुआ है, जिससे प्रकाशन रुका हुआ है. जनरल नरवणे ने अब फिक्शन की ओर रुख कर लिया है और उनकी किताब 'द कैंटनमेंट कॉन्सपिरेसी' पिछले साल प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने कहा था- मैं आगे बढ़ चुका हूं.

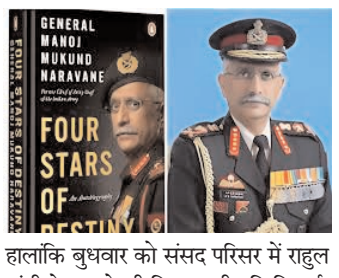

हालांकि बुधवार को संसद परिसर में राहुल गांधी ने नरवणे की किताब की प्रति दिखाई. इससे यह पूरा मामला और उलझ गया है. सवाल उठता है कि जब सरकार कह रही है कि यह किताब प्रकाशित ही नहीं हुई तो फिर यह किताब राहुल गांधी के हाथ में कैसे पहुंची. इस कारण लगातार तीन दिन से लोकसभा में हंगामा चल रहा है।

उस वक्त थी केंद्र मनमोहन सिंह की सरकार

खैर हम मेजरन जनरल वीके सिंह की कहानी पर लौटते हैं. द इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने उनकी इस जनरल की पूरी कहानी प्रकाशित की है. जनरल सिंह अब 81 वर्ष के हो चुके हैं. वह 2002 में रिटायर हुए थे. वह 2004 तक रॉ में डेपुटेशन पर रहे. उनकी किताब प्रकाशित होने के तुरंत बाद 2007 में सीबीआई ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया. जब यह मामला उजागर हुआ तब केंद्र में दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार थी. हालांकि इस केस से मनमोहन सरकार का कुछ सीधा लेना-देना था या नहीं. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है।

उनके गुरुग्राम स्थित घर पर छापा मारा गया और उनके कंप्यूटर, पासपोर्ट और डायरी जब्त कर लिए गए. आज भी वे जमानत पर हैं, लेकिन ट्रायल शुरू नहीं हुआ है. पिछले महीने उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची. इसमें उन्होंने मुकदमे के आधार पर दस्तावेजों की कॉपी मांगी है. सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2025 में CBI को नोटिस जारी किया था. जनरल सिंह ने शीर्ष अदालत में दिल्ली हाईकोर्ट के सितंबर 2025 के आदेश को चुनौती दी है।

सुप्रीम कोर्ट में चल रहा केस

हाईकोर्ट ने जनरल सिंह को सुबह 9 से रात 9 बजे के बीच दस्तावेजों की केवल इंस्पेक्शन की अनुमति दी थी. कोर्ट का मानना था कि इन दस्तावेजों के कुछ हिस्से भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित कर सकते थे. मेजर जनरल सिंह का कहना है कि 18 साल से अधिक समय से चल रहे मुकदमे से मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्ट हो रहा है और यह न्याय की अवधारणा को कमजोर कर रहा है।

मेजर जनरल सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि रिटायर्ड आर्मी अधिकारियों पर कोई गैग ऑर्डर या किताब मैनुस्क्रिप्ट रिव्यू के लिए सबमिट करने का लिखित निर्देश नहीं है. उन्होंने बताया कि 1954 के आर्मी रूल्स की धारा 21 केवल सर्विंग पर्सनल पर लागू होती है. सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स IB और BSF जैसे एजेंसियों के रिटायर्ड कर्मचारियों पर लागू होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस पर नहीं।

क्या हैं नियम

उन्होंने बताया कि 2021 के संशोधित नियम केवल सिविलियन ऑफिसर्स पर लागू होते हैं. उन्होंने कहा कि उनकी किताब में RAW में भ्रष्टाचार के संभावित क्षेत्रों को व्हिसलब्लोअर की तरह उजागर किया गया था. CBI ने किताब में कई सीक्रेट रिवीलेशन्स को आधार बनाया, जैसे RAW के चार्टर, ड्यूटीज, टेक्निकल कैपेबिलिटी अपग्रेड और कुछ स्टेशनों के लोकेशन. मेजर जनरल सिंह का मानना है कि उनकी केस ने रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल में डर पैदा कर दिया है. कई अधिकारी रॉ, एनटीआरओ या जीआरडीओ में डेपुटेशन पर जाते हैं, लेकिन अब संवेदनशील विषयों पर किताब लिखने से बचते हैं. पिछले दो दशक में कई रिटायर्ड आर्मी और रॉ अधिकारियों ने किताबें प्रकाशित कीं, लेकिन मुश्किल से किसी ने मैनुस्क्रिप्ट क्लियरेंस के लिए सबमिट की।

बिहार चुनाव के ख़िलाफ़ जन सुराज पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, नए सिरे से चुनाव कराने की मांग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा गठित जन सुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हुई कथित अवैध प्रक्रियाओं को चुनौती देते हुए नए सिरे से चुनाव कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है. पार्टी ने विशेष रूप से राज्य में महिला मतदाताओं को कथित तौर पर आचार संहिता लागू होने के दौरान 10,000 रुपये के सीधे ट्रांसफर को चुनौती दी है. इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ शुक्रवार (6 फरवरी) को करेगी।

अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि आचार संहिता लागू रहने के दौरान राज्य में महिलाओं को सीधे 10,000 रुपये की राशि भेजी गई, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 112, 202 और 324 का उल्लंघन है. जन सुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 (भ्रष्ट आचरण) के तहत बिहार चुनावों में 25-35 लाख महिला मतदाताओं को सीधे

10,000 रुपये ट्रांसफर करने के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि 25 से 35 लाख महिला मतदाताओं को सीधे पैसे दिया जाना चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करता है. इसके अलावा दोनों चरणों के मतदान के दौरान स्वयं सहायता समूह जीविका से जुड़ी लगभग 1.8 लाख महिला लाभार्थियों की मतदान केंद्रों पर तैनाती को भी अवैध और अनुचित बताया गया है।

दोबारा चुनाव की मांग

याचिकाकर्ता ने कथित भ्रष्टाचार के मद्देनजर बिहार में नए सिरे से विधानसभा चुनाव कराने का अनुरोध करते हुए चुनाव आयोग को एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य (2013) 9 एससीसी 659 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने और मुफ्त योजनाओं, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाओं आदि पर व्यापक दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश देने की भी मांग की है।

याचिकाकर्ता ने यह भी आग्रह किया है कि चुनाव आयोग सत्ताधारी राजनीतिक दलों द्वारा निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर प्रभाव डालने वाली योजनाओं, जैसे कि मुफ्त सहायता, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं आदि को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले लागू करने के लिए कम से कम छह महीने का समय निर्धारित करे।

गौरतलब है कि बिहार में 1.21 करोड़ महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना के तहत दस-दस हज़ार रुपये बांटे गए थे. ये राशि चुनाव से ठीक पहले वितरित की गई थी. इस पूरे प्रकरण पर चुनाव आयोग की निष्क्रियता को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हुए. लेकिन नीतीश सरकार की इस योजना ने एनडीए को चुनाव में भारी बढ़त दिलाई. चुनावी नतीजों ने भी बताया कि नीतीश कुमार की ताक़त मानी जाने वाली महिला वोटरों को इस योजना ने और मजबूती के साथ उनकी तरफ़ किया. शुरुआत में यह योजना आजीविका से जुड़े काम करने वाली महिलाओं के लिए शुरू की गई थी, बाद में इसे अन्य महिलाओं पर भी लागू किया गया।

संक्षिप्त ख़बरें

मेघालय में कोयले की खदान में हुआ भीषण विस्फोट, 10 मजदूरों की हुई मौत

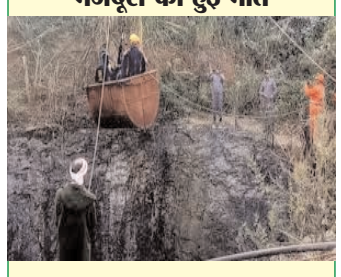

मेघालय के ताशखाई इलाके में स्थित एक कोयला खदान में गुरुवार (5 फरवरी 2026) को हुए भीषण विस्फोट हुआ। इस हादसे में 10 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। यह धमाका इतना जोरदार था कि खदान के भीतर काम कर रहे मजदूरों को संभलने तक का मौका नहीं मिला।घटना के बाद पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल है और स्थानीय प्रशासन ने बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है।

क्या है पूरा मामला?

सामने आई जानकारी के अनुसार, ताशखाई की इस खदान में मजदूर रोजाना की तरह खुदाई का काम कर रहे थे, तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। आशंका जताई जा रही है कि धमाका खदान के भीतर गैस रिसाव या विस्फोटक सामग्री के गलत इस्तेमाल के कारण हुआ हो सकता है। शुरुआती जांच में पता चला है कि मरने वाले अधिकांश मजदूर असम के रहने वाले थे। इनमें से एक की पहचान असम के कटिगारा क्षेत्र के बिहारा गांव के निवासी के रूप में हुई है। मेघालय पुलिस और बचाव दल मलबे में फंसे अन्य संभावित मजदूरों की तलाश में जुटे हैं।

अवैध खनन और सुरक्षा पर उठे सवाल

इस हादसे ने एक बार फिर मेघालय में चल रहे अवैध 'रैट-होल' (Rat-hole) माइनिंग और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को उजागर कर दिया है। प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि खदानों में सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे।

प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई

पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है ताकि बचाव कार्य में बाधा न आए। धमाके के कारणों की तकनीकी जांच (Technical Investigation) शुरू की गई है। सरकार ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और मृतकों के परिवारों को उचित मुआवजे का आश्वासन दिया है।

BSF को जमीन दे दी, फिर भी बाड़ अधूरी क्यों? BSF और फंड को लेकर ममता बनर्जी ने बोला केंद्र पर हमला

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. तो वहीं केंद्र सरकार भी ममता पर कई बार आरोप लगा चुकी है कि वे बीएसएफ के लिए जमीन नहीं देती हैं. केंद्र के इन आरोपों पर ममता ने कहा कि केंद्रीय संगठनों और बीएसएफ को जमीन मुहैया कराई गई है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय संगठनों और बीएसएफ को जमीन मुहैया कराई गई है. लेकिन, सीमा पर बाड़ लगाने का काम आज भी अधूरा है. ममता ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 से 50 किलोमीटर करने के मनमाने नियम को तुरंत बदलने की मांग की. उन्होंने यह भी दावा किया कि केंद्र सरकार पर बंगाल का 2 लाख करोड़ रुपये बकाया है।

पश्चिम बंगाल में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं. वैसे-वैसे सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है. ममता बनर्जी

सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला बोल रही हैं.

बहुत देखे हैं गृह मंत्री- ममता बनर्जी

ममता बनर्जी ने गृह मंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि मीटिंग में बॉर्डर के बारे में आप मौजूद नहीं थे. मैंने उनके जैसे कई गृह मंत्री देखे हैं, मुझे गृह मंत्री मत दिखाओ. पहले डेटा शेयर किया जाता था, अब डेटा शेयर नहीं किया जाता. मैंने सभी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन को जमीन दी है. पहले अपना काम करो, बाकी दे दिया जाएगा।

ममता ने कहा कि मैंने कोल इंडिया, सेल, भेल, बीएसएफ, सीआईएसएफ को ज़मीन दी है, आप अपना काम खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं?

घुसपैठिए वाले मुद्दे पर क्या बोंली ममता?

पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले घुसपैठिए वाला मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इसको लेकर बीजेपी ममता सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगा रही है. इसी को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि अगर घुसपैठिए हैं. आपके प्रधानमंत्री इसी वोटर लिस्ट के भरोसे जीते हैं. प्रधानमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं?

पैसा मिलने पर मान लेंगे सभी मांग- ममता

उन्होंने कहा कि चोरों की मां ज्यादा बोलती है. आपने गंगासागर या गाथल मास्टर प्लान के लिए एक भी पैसा नहीं दिया है. हमें सेंट्रल सरकार से 2 लाख करोड़ रुपये मिलने हैं. जब हमें पैसे मिल जाएंगे तो हम आपकी सभी मांगें मान लेंगे. हम कोर्ट में भी जीतते हैं और वोट में भी जीतते हैं।

44 साल पुराना मर्डर केस, 100 साल का आरोपी, इलाहाबाद HC से अब हुआ बरी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

एक हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए शख्स को जिंदगी के 100 वसंत देखने के बाद जाकर अब कोर्ट से इंसाफ मिल सका. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल बुधवार को मर्डर केस के करीब 100 साल के आरोपी को बरी कर दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उसकी ओर से उम्रकैद की सजा को चुनौती दिए हुए चार दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है और उसे राहत देते समय उसके द्वारा झेले गए सामाजिक नतीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

जस्टिस चंद्र धारी सिंह और जस्टिस संजीव कुमार की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाते हुए यह भी कहा कि अपील का लंबे समय तक लंबित रहना और आरोपी धनी राम की लंबी उम्र को देखते हुए राहत देना प्रासंगिक है. 1984 में सुनाई गई थी उम्र कैद की सजा।

मामला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले का है. साल 1982 में यह हत्या जमीन से जुड़े एक विवाद को लेकर हुई थी, और इस मामले में 3 लोग मैकू, सत्ती दीन और धनी राम आरोपी बनाए गए. हत्याकांड के बाद मैकू फरार हो गया था, जबकि हमीरपुर सेशंस कोर्ट ने 2 साल बाद 1984 में सत्ती दीन और धनी राम को उम्रकैद की सजा सुना दी थी. धनी राम को उसी साल जमानत पर रिहा कर दिया गया था. जबकि सत्ती दीन की अपील लंबित रहने के दौरान मौत हो गई, ऐसे में राम इस केस में एकमात्र जीवित अपीलकर्ता रह गया।

अभियोजन पक्ष शक साबित नहीं कर सकाः HC

यह देखते हुए कि राम तब से जमानत पर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि उसकी जमानत बॉन्ड को खत्म कर दिया जाए और यह भी कहा कि आरोपी को बरी करने का फैसला मामले की खूबियों पर आधारित है, खासकर अभियोजन पक्ष के आरोपों को उचित संदेह से परे साबित करने में नाकामी को देखते हुए. फैसला सुनाते समय डिवीजन बेंच ने आगे यह भी कहा कि दशकों से आरोपी द्वारा झेली गई चिंता, अनिश्चितता और सामाजिक नतीजों को आकलन करते समय इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि अब इस केस में न्याय क्या मांगता है. धनी राम के वकील ने सुनवाई के दौरान कोर्ट से कहा कि अपीलकर्ता की उम्र करीब 100 साल है और उसने केवल मैकू को पीड़ित पर गोली चलाने के लिए उकसाया था।

'2017 से पहले योजना का लाभ बिचौलिए लेते थे...BJP सरकार ने कसी लगाम', ष्टरूयोगी का दावा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

उत्तर प्रदेश के सहकारी,एमएसएमई क्षेत्र में 2017 के बाद से बड़ा बदलाव आया है. मौजूदा सरकार के स्पष्ट इरादे ने जमीनी स्तर पर स्पष्ट परिणाम दिए हैं. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये दावा किया है. सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले एमएसएमई क्षेत्र में राज्य की हालत बेहद खस्ता थी. हर तरफ लूटमार का माहौल था. एक तरह से इस पर पूरी तरह से माफिया काबिज थे, लेकिन बीजेपी सरकार बनने के बाद इस क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है. स्टेट क्रेडिट सेमिनार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले जो स्थिति थी उसने राज्य से बड़े पैमाने पर पलायन को मजबूर किया था. कारीगर निराश थे और एमएसएमई क्षेत्र ढहने की कगार पर था. सरकार ने प्रोत्साहन दिया और एक जिला, एक उत्पाद पहल के जरिये इसे बढ़ावा दिया. ष्टरूयोगी ने सपा पर हमला बोलते हुए दावा किया कि 2017 से पहले, न तो विकास था और न ही रोजगार. योजना का लाभ बिचौलिए लेते थे. सहकारी क्षेत्र पर ऐसे लोग काबिज थे जो माफिया से कम नहीं थे. उस समय विकास और रोजगार के अवसरों की कमी थी और सहकारी क्षेत्र अस्त-व्यस्त था. सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद इस क्षेत्र में व्यापक स्तर पर सुधार किया गया है।

16 जिला सहकारी बैंकों में से 15 मुनाफे में

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उस समय भारतीय रिजर्व बैंक

(आरबीआई) ने 16 जिला सहकारी बैंकों को चूककर्ता (डिफॉल्टर) घोषित किया था. आज, इन 16 जिला सहकारी बैंकों में से 15 मुनाफे में आ गए हैं. बचे हुए एक को भी मुनाफे में लाने की कोशिश जारी है. उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) को मजबूत किया है. इस दौरान सीएम द्वारा स्टेट फोकस पेपर 2026-27 भी जारी किया गया।

मौजूदा सरकार की नियत साफ

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पैक्स की संख्या बहुत अधिक है. हमने उनका टर्नओवर बढ़ाया है, उनकी ऋण सीमा बढ़ाई है और उन्हें खाद वितरण के काम में शामिल किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी विभाग में कर्मचारियों की कमी के बावजूद उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे अच्छे खाद वितरण प्रणालियों में से एक हासिल किया है. उन्होंने कहा कि कृषि और सहकारिता विभागों के बीच तालमेल से सहकारी समितियां एक बार फिर नए जन आंदोलन के रूप में उभरी हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब देश का पहला राज्य है जो अपने एमएसएमई क्षेत्र को पांच लाख रुपये तक का बीमा कवर दे रहा है. उन्होंने कहा कि जब सरकार की नीयत साफ होती है, तो नतीजे भी साफ दिखते हैं।

मणिपुरः उपमुख्यमंत्री नेमचा किपगेन ने दिल्ली से ऑनलाइन शपथ ली, पद लेने से नाराज़ कुकी-ज़ो समुदाय

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- 'तुम्हारे हाथों पर खून है, गद्दार नेमचा किपगेन.' यह नारा बुधवार (4 फरवरी) को दिल्ली में मणिपुर की उपमुख्यमंत्री के रूप में किपगेन की नियुक्ति के कुछ ही घंटों के भीतर कुकी-ज़ो समुदाय के सदस्यों के बीच गूंजने लगा. यह उनके अपने ही समुदाय के कुछ वर्गों में फैले गहरे गुस्से और विश्वासघात की भावना को दिखाता है. मणिपुर, जो लंबे समय से चल रही जातीय हिंसा के बीच लगभग एक साल से राष्ट्रपति शासन के अधीन था, आखिरकार राज्य की राजधानी इंफाल में नए मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह के नेतृत्व में एक चुनी हुई सरकार की वापसी हुई, लेकिन यह बिना विवाद के नहीं हुआ. समावेशिता का संदेश देने की कोशिश में भाजपा ने कुकी-ज़ो समुदाय के कुछ विधायकों को नई सरकार में शामिल किया. हालांकि, कई कुकी-ज़ो लोगों के लिए इस कदम ने घावों को भरने के बजाय उन्हें और गहरा कर दिया है।

दिल्ली में करीब 50 कुकी-ज़ो लोग मणिपुर भवन के बाहर इकट्ठा हुए और किपगेन के तत्काल इस्तीफे की मांग की. उनका आरोप था कि किपगेन ऐसी सरकार को वैधता दे रही हैं, जिसने उनके लोगों को निराश किया है. बुधवार को मणिपुर के लोक भवन में खेमचंद सिंह ने मुख्यमंत्री और नगा पीपुल्स फ्रंट के विधायक लोसी दीखो ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. लेकिन किपगेन ने उपमुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली के मणिपुर भवन से ऑनलाइन शपथ ली, न कि मेईतेई बहुल इंफाल घाटी में, जहां उनकी कुकी-ज़ो समुदाय के सदस्य मई 2023 में शुरू हुई जातीय हिंसा के बाद से अब भी नहीं जा पा रहे हैं।

इसके साथ ही कोंथौजम गोविंदास सिंह और खुरैजम लोकेन सिंह ने भी नई सरकार में मंत्री के रूप में शपथ ली. शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री ने इंफाल में अपने बंगले में कैबिनेट बैठक की. इससे कुछ घंटे पहले ही राष्ट्रपति ने मणिपुर में केंद्र सरकार का शासन (राष्ट्रपति शासन) हटा लिया था और सिंगजामेई सीट से विधायक, मेईतेई नेता खेमचंद सिंह ने राज्यपाल अजय भल्ला से मिलकर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया था. बुधवार शाम मणिपुर भवन के बाहर खड़े प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि किपगेन ने 'अपने समुदाय के बजाय उपमुख्यमंत्री का पद चुन लिया है.' प्रदर्शनकारियों में शामिल होइनु ने कहा, 'हमारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, उनकी हत्या की गई, हमारे घर जला दिए गए. पूरी की पूरी पीढ़ियां तबाह हो गई हैं. वह हमारे साथ ऐसा विश्वासघात कैसे कर सकती हैं? वह कुकी समुदाय की नेता हैं, वह अकेले ऐसा फैसला नहीं ले सकती थीं. उन्हें मणिपुर के लोगों से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि हम मेईतेई लोगों के साथ नहीं रह सकते. हमारे लिए साथ रहने का मतलब मौत है.' होइनु कभी इंफाल में रहा करती थीं, लेकिन मई 2023 के बाद से उन्होंने अपना घर नहीं देखा है. जब जातीय हिंसा शुरू हुई थी, तब उनका परिवार शहर छोड़कर चला गया था. 33 महीने बाद भी मेईतेई और कुकी-ज़ो लोग लगभग पूरी तरह अलग-थलग हैं, जिन्हें इंफाल घाटी

और आसपास की पहाड़ियों को अलग करने वाले सुरक्षा बलों द्वारा बनाए गए बफर ज़ोन ने बांट रखा है. कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन-एनसीआर के अध्यक्ष टिंगबेम ने कहा, 'जब हमारे लोगों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, काट डाला गया या मार दिया गया, तब उन्होंने (किपगेन) कभी आवाज़ नहीं उठाई. अब वह हमारी नेता बनने आगे आ रही हैं? नहीं. उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वह हमारी प्रतिनिधि नहीं हैं.' मंगलवार को नई सरकार के गठन को अंतिम रूप देने के लिए मणिपुर के सभी भाजपा विधायक और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के नेता दिल्ली बुलाए गए थे. केंद्र सरकार ने कुकी-ज़ो विधायकों के साथ अलग-अलग बैठकें भी कीं।

60 सदस्यीय विधानसभा में कुकी-ज़ो समुदाय के 10 विधायक हैं, जिनमें से पांच ने मंगलवार की बैठक में हिस्सा लिया. फिलहाल मणिपुर में भाजपा के सात कुकी-ज़ो विधायक हैं, जिनमें नेमचा के अलावा एलएम खाउते और न्गुरसांगलुर सनाते भी नई सरकार के गठन का समर्थन कर रहे हैं. बुधवार के शपथ ग्रहण से पहले कई कुकी-ज़ो नेताओं ने 'गुवाहाटी घोषणा' का हवाला दिया, जिसे नागरिक संगठनों, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस समझौते के तहत आने वाले उग्रवादी समूहों और समुदाय के विधायकों ने अपनाया था. इसमें यह तय किया गया था कि जब तक केंद्र सरकार पहाड़ी इलाकों के लिए विधायिका के साथ एक अलग प्रशासन - यानी एक केंद्र शासित प्रदेश - को मंजूरी नहीं देती, तब तक किसी लोकप्रिय सरकार में भाग नहीं लिया जाएगा।

कुकी-ज़ो काउंसिल के नेता गिन्ज़ा वुअलज़ोंग ने कहा था कि इस रुख से कोई भी बदलाव व्यक्तिगत फैसला होगा. उन्होंने कहा, 'अगर नेमचा किपगेन गुवाहाटी प्रस्ताव को नजरअंदाज करती हैं, तो वह अपने दम पर आगे बढ़ रही हैं और अपने जोखिम पर ऐसा कर रही हैं.' ज्ञात हो कि लगातार जारी जातीय हिंसा को देखते हुए 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था. इस संघर्ष में अब तक 270 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं. बुधवार को मणिपुर भवन के बाहर जुटे लोग बार-बार मांग कर रहे थे कि किपगेन बाहर आएं और उनके सवालों का जवाब दें. हालांकि, मौके पर मौजूद अधिकारियों ने किसी भी तरह की बातचीत की अनुमति नहीं दी और प्रदर्शनकारियों से वहां से हटने को कहा गया. जैसे-जैसे प्रदर्शन जारी रहा, प्रदर्शनकारियों ने उपमुख्यमंत्री की तस्वीर वाले पोस्टरों को आग के हवाले कर दिया. इसके तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने हस्तक्षेप किया और प्रदर्शनकारियों से परिसर छोड़ने को कहा, जिसके बाद यह प्रदर्शन समाप्त हो गया।

दिव्यांग-जनों को उत्तरोत्तर अवसर दिए जाने की प्रतीक्षा

दिव्यांगों की जिजीविषा सर्व अनुकरणीय।

भारत में दिव्यांगता केवल एक सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास की एक महत्वपूर्ण वास्तविकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व स्तर पर लगभग हर छह में से एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की दिव्यांगता के साथ जीवन यापन कर रहा है। विश्व में ऐसे लोग एक अरब से अधिक है। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र भी मानता हैं कि दुनिया भर में दिव्यांगजन की जनसंख्या इतनी बड़ी है कि सामाजिक समावेशन और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता मिले तभी विश्व की प्रगति पूर्ण हो सकती है। भारत की स्थिति पर ध्यान दें तो 2011 की आधिकारिक जनगणना के अनुसार देश में लगभग 2.68 करोड़ व्यक्ति दिव्यांगता के अंतर्गत आते हैं, जो कुल जनसंख्या का लगभग 2.21% हिस्सा है। परंतु मध्य सर्वेक्षण और स्वास्थ्य समीक्षाएं संकेत देती हैं कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है और कुछ सर्वे के मुताबिक यह लगभग 4% से अधिक अनुमानित है, क्योंकि परंपरागत डेटा इकठ्ठा करने के तरीकों में कई लोग दर्ज नहीं होते। भारत जैसे विविध और बड़े देश में यह संख्या केवल एक आंकड़ा नहीं है, यह हर वर्ग, क्षेत्र और सामाजिक स्तर पर फैली एक चुनौती और अवसर दोनों है।

दिव्यांगता का मतलब है किसी व्यक्ति के शारीरिक या मानसिक क्षमता में दीर्घकालिक कमी, जो उसके दैनिक जीवन और सामाजिक सहभागिता को बाधित करती है। यह शारीरिक अक्षमता, दृष्टिहीनता, श्रवणक्षमता, भाषण से जुड़ी असमर्थता, मानसिक विकलांगता, बहु दिव्यांगता आदि कई रूपों में हो सकती है। यह सीमा केवल चिंतन के आयामों तक सिमित नहीं है, बल्कि सामाजिक ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आत्मनिर्भरता जैसे सबसे बुनियादी मूल्यों को प्रभावित करती है।

भारत सरकार ने इस संवेदनशील विषय पर कई ऐतिहासिक निर्णय और सुधार किए हैं। 1995 में विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम पारित हुआ और 1996 में लागू कर दिया गया, जो दिव्यांगजन के लिए शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और आरक्षण जैसे प्रावधानों को शामिल करता है। यह कानून समाज की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है और दिव्यांगता को एक अधिकार-आधारित दृष्टिकोण से परिभाषित करता है, जहां दिव्यांगजन को समान अवसर और सम्मान मिले। इसके उपरांत 1999 में राष्ट्रीय स्थायी न्यास बनाया गया ताकि दिव्यांगजन की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान के लिए एक औपचारिक मंच हो।

2012 में केंद्र सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को स्थापित किया, जिसका उद्देश्य दिव्यांगों के लिए अलग से योजनाएँ, नीति और उनके समावेशन को सुनिश्चित करना है। 2016 में पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया, जिसने दिव्यांगता की परिभाषा को और विस्तृत कर दिया तथा 21 प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता दी। इसके साथ ही दिव्यांगजन के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, तकनीकी सहायता और रोजगार में सुधार की कई नई धारणाएँ लाई गई।

शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने 2015 में दिव्यांगजन की शिक्षा नीति को अपनाया, जिसमें उनके लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और समतुल्य अवसर प्रदान करने का प्रावधान रखा गया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन पुस्तकालय, सुगम्य सीख जैसे कोर्स शुरू किए गए ताकि बटन क्लिक से ही दिव्यांग छात्र पुस्तकों और संसाधनों तक पहुँच सकें। साथ ही 2016 में दिव्यांग अधिकारिता विभाग की सलाह से एक जॉब पोर्टल भी लॉन्च हुआ, जो नौकरी के अवसर, स्वरोजगार ऋण, शिक्षा ऋण और कौशल प्रशिक्षण जैसी सेवाएँ एकल मंच पर प्रदान करता है, जिससे दिव्यांगजन की आर्थिक भागीदारी और आत्मनिर्भरता बढ़ सके।

समाज और सरकार का समन्वय जब अपने चरम पर होता है तो महान उपलब्धियाँ सामने आती हैं। 2017 में दिव्यांग साथी मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की योजनाओं, नियमों, छात्रवृत्तियों, रोजगार-संबंधी अवसरों की सरल एवं सीधी जानकारी प्रदान करना है ताकि वास्तविक सशक्तिकरण को धरातल पर लागू किया जा सके। 2026 के भारत के बजट में भी दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांग कौशल योजना और दिव्यांग सहारा योजना जैसी योजनाओं की घोषणा की गई, जो कौशल विकास, सम्मानजनक आजीविका और आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध कराने पर केंद्रित हैं।

स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में हालांकि कई सुधार हुए हैं, कुछ चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। उदाहरण के तौर पर एक ताज़ा सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि लगभग 82% दिव्यांगजन के पास कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है, और लगभग 42% को आयुष्मान भारत जैसी प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी भी नहीं है, जिससे उनके लिए स्वास्थ्य सेवा की पहुँच सीमित रह जाती है। इस दिशा में सुधार की आवश्यकता है ताकि स्वास्थ्य सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हो सकें।

अक्षर सत्ता रोजगार और आर्थिक समावेशन की दिशा में भी गति आई है, परंतु आंकड़े बताते हैं कि भारत में लगभग 1.3 करोड़ दिव्यांग रोजगार योग्य हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ लाख ही रोजगार पा रहे हैं। निजी क्षेत्र में दिव्यांगों को नौकरी देने के नियम व्यापक रूप से लागू नहीं होते या कंपनियाँ जुर्माना देकर इन नियमों से बचने का चुनाव करती हैं, जिससे आत्म-निर्भरता के अवसर कम होते हैं।

क्रीड़ा और सामाजिक उपलब्धियाँ इन कठिनाइयों के बावजूद दिव्यांगजन की जिजीविषा का प्रदर्शन हैं। भारतीय दिव्यांग खिलाड़ियों ने कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते हैं, जिससे देश का नाम विश्व मंच पर चमका। पैरा ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों का प्रदर्शन, और क्रिकेट, एथलेटिक्स, निशानेबाजी और अन्य खेलों में उनके उपलब्धियाँ स्थापित करती हैं कि दिव्यांगता क्षमता की कमी नहीं, बल्कि सामाजिक अवरोधों के प्रतिबिंब मात्र है।

ऐसी प्रेरणाएँ अनेक हैं जैसे अरुणिमा सिन्हा जिन्होंने प्रथम भारतीय विकलांग महिला के रूप में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा; पैरालंपिक में दीपा मलिक व देवेंद्र झाझरिया जैसे खिलाड़ियों ने पदक हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया; साथ ही कला, संगीत, चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में भी दिव्यांगजनों ने अपनी पहचान बनायी है। दिव्यांगजन में अपार क्षमता है और वे समाज के प्रेरणा स्रोत हैं, बशर्ते उन्हें अवसर, सम्मान और सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएं। इसके लिए केवल शासन ही नहीं, स्वास्थ्य पेशेवर, शिक्षक, सामाजिक संस्थाएँ, स्वयंसेवी समूह और आम नागरिक सबको आगे आकर समावेशी समाज की दिशा में मिलकर कार्य करना होगा। यही वह मार्ग है जो दिव्यांगजन को मुख्यधारा में पूर्ण रूप से जोड़ कर भारत को सामाजिक समरसता, गरिमा और प्रगति की ऊँचाइयों तक ले जाएगा।

संजीव ठाकुर

अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे

भारत और अमेरिका के बीच हाल में हुए व्यापारिक समझौते ने केवल दो देशों की नीतियों को ही नहीं बदलाए बल्कि वैश्विक राजनीति के समीकरणों को भी नई दिशा दी है। जिस अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान आयात शुल्क को हथियार बनाकर पूरी दुनिया को चेतावनी दी थीए वही ट्रंप अचानक भारत के मामले में नरम पड़ते दिखाई दिए। जिन शुल्कों को उन्होंने पहले पचास प्रतिशत तक पहुँचा दिया थाए उन्हें घटाकर अठारह प्रतिशत पर लाना कोई सामान्य फैसला नहीं था। यह बदलाव न तो अचानक हुआ और न ही एकतरफा दबाव का परिणाम था। इसके पीछे भारत की एक सधी हुईए दूरदर्शी और संतुलित कूटनीति काम कर रही थीए जिसने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को भी बातचीत की मेज पर सम्मान के साथ बैठने को मजबूर कर दिया।

ट्रंप की राजनीति हमेशा आक्रामक रही है। उनका मानना रहा कि आर्थिक दबाव के जरिए ही किसी देश को झुकाया जा सकता है। सत्ता में आते ही उन्होंने चीन के साथ व्यापार युद्ध छेड़ दिया और उसी क्रम में भारत को भी निशाने पर लिया। भारत पर यह आरोप लगाया गया कि वह विदेशी वस्तुओं पर बहुत अधिक कर लगाता है और अमेरिकी कंपनियों को उचित अवसर नहीं देता। इसी सोच के तहत भारत को विशेष व्यापारिक सुविधा की सूची से बाहर कर दिया गयाए जिससे भारतीय निर्यातकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस फैसले से दवाइयोंए कपड़ोंए रत्नों और कृषि उत्पादों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा और भारत के लिए अमेरिकी बाजार कठिन हो गया।

भारत ने इस दबाव को चुपचाप स्वीकार नहीं किया। उसने जवाबी कदम उठाए और अमेरिका से आने वाले कई उत्पादों पर कर बढ़ा दिए। इससे अमेरिका के किसान और उद्योगपति प्रभावित हुए। बादामए सेब और अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात पर असर पड़ा। यह संकेत साफ था कि भारत केवल सुनने वाला देश नहीं हैए बल्कि अपने हितों की रक्षा करना जानता है। इसके बावजूद भारत ने टकराव की भाषा नहीं अपनाई। उसने संवाद के दरवाजे खुले रखे और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का मूल आधार संतुलन रहा है। न तो किसी के आगे झुकना और न ही अनावश्यक टकराव। इसी नीति के तहत भारत ने अमेरिका के साथ रणनीतिक सहयोग बढ़ाया। सुरक्षाए रक्षा उत्पादनए तकनीक और निवेश के क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत किया गया। भारत ने यह संदेश स्पष्ट रूप से दिया कि वह केवल एक बाजार नहींए बल्कि भरोसेमंद साझेदार है। अमेरिका की बड़ी कंपनियों को भारत में निवेश के अवसर दिए गएए उत्पादन को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के माध्यम से उद्योगों को आकर्षित किया गया और नौकरशाही अड़चनों को कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए।

इन सभी प्रयासों का असर तब दिखा जब ट्रंप ने खुद स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के बाद उन्होंने अपने रुख पर पुनर्विचार किया। यह कोई साधारण फोन वार्ता नहीं थीए बल्कि वर्षों की रणनीति और विश्वास का परिणाम थी। ट्रंप जैसे नेताए जो आमतौर पर सार्वजनिक रूप से किसी की प्रशंसा नहीं करतेए उन्होंने मोदी को प्रभावशाली और सम्मानित नेता बताया। यह बदलाव केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहाए बल्कि नीतियों में भी दिखाई दिया। नए व्यापारिक समझौते के तहत भारत और अमेरिका दोनों ने एक दूसरे को राहत दी। भारत ने कुछ कृषि उत्पादों पर शुल्क कम करने का संकेत दियाए जबकि अमेरिका ने भारतीय इस्पातए कपड़ा और दवा उद्योग को बड़ी राहत दी। इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और लाखों लोगों के रोजगार सुरक्षित होंगे। दवा उद्योग के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैए क्योंकि भारतीय दवाइयाँ सस्ती और प्रभावी मानी जाती हैं और अमेरिका में उनकी मांग लगातार बढ़ रही है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा सवाल यह भी उठा कि क्या अमेरिका से बढ़ती नजदीकी का असर भारत के रूस के साथ संबंधों पर पड़ेगा। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से सस्ता तेल खरीदने के कारण भारत पश्चिमी देशों की आलोचना के केंद्र में रहा है। भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए रूस से तेल खरीद जारी रखीए जिससे उसे अरबों रुपये की बचत हुई और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई। अमेरिका ने इस पर असंतोष जरूर जतायाए लेकिन कोई ठोस प्रतिबंध नहीं लगाया।

रूस की ओर से भी यह स्पष्ट किया गया कि भारत के साथ उसके संबंधों में कोई बदलाव नहीं आया है। रूसी नेतृत्व ने कहा कि भारत एक भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार है और दोनों देशों का सहयोग आगे भी जारी रहेगा। रक्षा क्षेत्र में चल रही परियोजनाएँए मिसाइल प्रणालियों की आपूर्ति और सैन्य सहयोग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह प्रतिक्रिया इस बात का प्रमाण है कि भारत ने अपनी कूटनीति में संतुलन बनाए रखा है और किसी एक खेमे में खुद को सीमित नहीं किया है।

भारत की यह नीति कोई नई नहीं है। आज़ादी के बाद से ही भारत ने गुटनिरपेक्षता और रणनीतिक स्वायत्तता का रास्ता चुना है। बदलती दुनिया में शब्द भले बदल गए होंए लेकिन मूल भावना वही है। भारत अपने फैसले स्वयं करता हैए दबाव में नहीं। अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौता भी इसी सोच का परिणाम है। इसमें न तो आत्मसमर्पण है और न ही टकरावए बल्कि आपसी लाभ का रास्ता है।

इस समझौते का असर केवल भारत और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी इसके सकारात्मक संकेत दिखाई देंगे। जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ सहयोग का रास्ता चुनती हैंए तो बाजारों में स्थिरता आती है। निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और विकास को गति मिलती है। भारत के लिए यह अवसर है कि वह खुद को विश्व उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित करे और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करे।

हालांकि चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। डिजिटल करए बौद्धिक संपदा अधिकार और आंकड़ों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। भारत को सावधानी से आगे बढ़ना होगा ताकि घरेलू हितों की अनदेखी न हो। विदेशी कंपनियों को अवसर देते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि देश के कानूनों और संप्रभुता से कोई समझौता न हो।

राजनीतिक दृष्टि से भी यह समझौता महत्वपूर्ण है। इससे यह संदेश जाता है कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहींए बल्कि वैश्विक नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की यह एक बड़ी परीक्षा थीए जिसमें वे सफल दिखाई देते हैं। ट्रंप का नरम रुख इस बात का संकेत है कि भारत की बात अब सुनी जाती है। आने वाले वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग और गहरा हो सकता है। उभरती तकनीकोंए रक्षा उत्पादन और निवेश के क्षेत्रों में नए रास्ते खुलेंगे। साथ ही रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा सहयोग भी जारी रहेगा। भारत दोनों शक्तियों के साथ अपने हितों के अनुसार संबंध बनाए रखेगा। अंततः यह कहानी किसी की हार या जीत की नहीं हैए बल्कि बदलती दुनिया में समझदारी भरी कूटनीति की है। यह दिखाती है कि शोर मचाने से नहींए बल्कि संवाद और संतुलन से बड़े फैसले लिए जाते हैं। भारत ने यही रास्ता चुना है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है।

महेन्द्र तिवारी

संपादकीय

भारत-अमेरिका ट्रेड डील, धैर्य, दूरदृष्टि और आर्थिक आत्मविश्वास की जीत

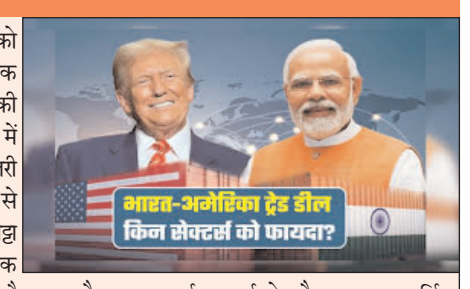

भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चली आ रही व्यापार वार्ताओं का सकारात्मक नतीजा सामने आना केवल एक समझौता भर नहीं है, बल्कि यह भारत की बदली हुई वैश्विक आर्थिक हैसियत, कूटनीतिक परिपक्वता और नीतिगत स्थिरता का प्रमाण है। टैरिफ दरों में 50 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत तक की कटौती के बाद जिस तरह से शेयर बाजार, कमोडिटी मार्केट और मुद्रा बाजार में उत्साह दिखा, उसने साफ कर दिया कि यह फैसला केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी अर्थव्यवस्था को गति देने वाला है। सेंसेक्स और निफ्टी का रिकॉर्ड तेजी के साथ बंद होना, निवेशकों की संपत्ति में एक ही दिन में करीब 12 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी और रुपये की तीन साल की सबसे बड़ी मजबूती, यह सब बाजार की उस भरोसे की अभिव्यक्ति है जो मौजूदा सरकार की आर्थिक नीतियों पर दिखाई देता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में इस समझौते को धैर्य और दूरदृष्टि का परिणाम बताया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आलोचनाएं होती रहीं, दबाव भी था, लेकिन सरकार ने राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बिना संयम बनाए रखा। आज उसी का परिणाम है कि भारत एक मजबूत सौदे की स्थिति में खड़ा है। यह बयान केवल राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि उन तथ्यों से भी पुष्ट होता है जो बाजार और वैश्विक संकेतकों में दिख रहे हैं। ट्रेड डील के ऐलान के तुरंत बाद निवेशकों का भरोसा बढ़ा, विदेशी संस्थागत निवेशकों की गतिविधियां तेज हुईं और घरेलू निवेशकों ने भी आक्रामक खरीदारी की।

विपक्ष की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि यह समझौता किसानों और घरेलू उद्योगों के हितों के खिलाफ है, लेकिन ये आरोप वास्तविकता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। सरकार ने साफ किया है कि कृषि और संवेदनशील क्षेत्रों में भारत के हितों की पूरी तरह रक्षा की गई है। किसी भी तरह का ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है जिससे भारतीय किसानों को नुकसान पहुंचे। वास्तव में, यह समझौता भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच सुनिश्चित करता है, जिससे कृषि उत्पादों के साथ-साथ मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र को भी लाभ होगा। यह कहना कि भारत ने दबाव में आकर रियायतें दी हैं, तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने जैसा है।

कमोडिटी बाजार की बात करें तो सोना और चांदी में आई तेजी यह दर्शाती है कि निवेशक इस समझौते को दीर्घकालिक रूप से सकारात्मक मान रहे हैं। बीते कुछ दिनों की गिरावट के बाद सोने के दामों में करीब 8,200 रुपये की बढ़ोतरी और चांदी में 14 प्रतिशत से अधिक का उछाल केवल सट्टा नहीं है, बल्कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता की उम्मीद का संकेत है। आम तौर पर जब निवेशकों को भविष्य पर भरोसा होता है, तो वे जोखिम और सुरक्षित निवेश दोनों में संतुलन बनाते हैं। यही रुझान इस समय भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहा है। रुपये में मजबूती भी इस पूरी तस्वीर का अहम हिस्सा है। डॉलर के मुकाबले रुपये की तीन साल की सबसे बड़ी बढ़त यह बताती है कि भारत की बाहरी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। विदेशी मुद्रा भंडार, चालू खाते का प्रबंधन और निर्यात संभावनाओं में सुधार, इन सभी का संयुक्त प्रभाव मुद्रा बाजार में दिखा है। यह मजबूती आयात लागत को नियंत्रित करने में मदद करेगी, जिससे महंगाई पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है। आम नागरिक के लिए इसका मतलब है कि ईंधन, खाद्य तेल और अन्य आयातित वस्तुओं की कीमतों पर दबाव कम हो सकता है।

सरकार का यह दावा भी महत्वपूर्ण है कि आने वाले वर्षों में भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार 500 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। यह लक्ष्य महत्वाकांक्षी जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिस तरह से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी जगह मजबूत की है, 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसे अभियानों के जरिए उत्पादन क्षमता बढ़ाई है, उससे यह लक्ष्य यथार्थवादी लगता है। अमेरिकी कृषि मंत्री के बयान को लेकर विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि किसी भी द्विपक्षीय समझौते में दोनों पक्षों को लाभ होता है। यदि अमेरिकी कृषि निर्यात बढ़ता है, तो भारतीय उपभोक्ताओं को भी प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बेहतर विकल्प मिलते हैं, जबकि भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में नई संभावनाएं मिलती हैं।

एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री का सांसदों से अनुशासन और सक्रियता पर जोर देना भी इस पूरे घटनाक्रम को व्यापक संदर्भ में देखने का संकेत है। सरकार केवल समझौते कर लेने से संतुष्ट नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना चाहती है कि संसद की कार्यवाही प्रभावी हो, नीतियों पर सार्थक चर्चा हो और बजट व आर्थिक फैसलों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचे। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की सोच को दर्शाता है। विपक्ष जहां हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति अपनाता है, वहीं सरकार का फोकस परिणाम और संवाद दोनों पर है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस समझौते के बाद उद्योग जगत से लेकर छोटे निवेशकों तक में एक नई ऊर्जा दिख रही है। अडाणी, रिलायंस और प्रमुख वित्तीय कंपनियों के शेयरों में आई तेजी केवल बड़े कॉरपोरेट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी देखने को मिला। इससे रोजगार सृजन, निवेश चक्र और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की संभावना बढ़ती है। यही कारण है कि बाजार विश्लेषक इसे पिछले कई महीनों की सबसे मजबूत रैली मान रहे हैं।

विपक्ष का यह कहना कि सरकार अमेरिका के दबाव में झुकी है, उस बदलते वैश्विक परिदृश्य को नजरअंदाज करना है जिसमें भारत अब केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक निर्णायक भूमिका निभाने वाला देश बन चुका है। जी-20 की अध्यक्षता से लेकर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अहम हिस्सेदारी तक, भारत की आवाज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। ऐसे में किसी भी समझौते को कमजोरी के चश्मे से देखना वास्तविकता से मुंह मोड़ने जैसा है।

कुल मिलाकर, भारत-अमेरिका ट्रेड डील एक ऐसे समय में सामने आई है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितताओं से जूझ रही है। इस माहौल में भारत का आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना, निवेशकों का भरोसा जीतना और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना, सरकार की नीतिगत स्पष्टता को दर्शाता है। यह समझौता केवल आज के बाजार आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक दिशा और वैश्विक भूमिका को नई ऊंचाई देने वाला कदम साबित हो सकता है।

कांतिलाल मांडोत

हवा-पानी-मिट्टी ही नहीं, अब रिश्ते भी प्रदूषित हो रहे हैं

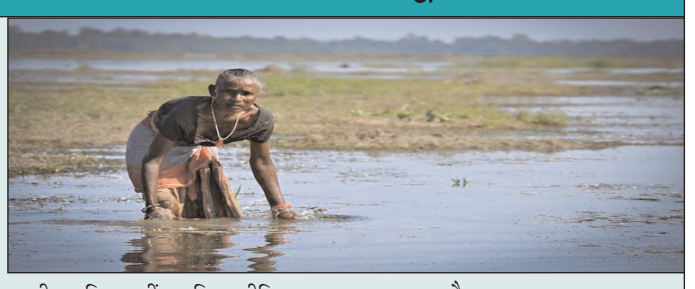

आज 'प्रदूषण' की चर्चा केवल वायु, जल या मृदा तक सीमित नहीं रही। यह धीरे-धीरे मानवीय संबंधों की उस पवित्र भूमि तक पहुँच चुका है, जहाँ कभी विश्वास, प्रेम, समर्पण और सहअस्तित्व के बीज बोए जाते थे। विडंबना यह है कि आज शायद ही कोई ऐसा रिश्ता बचा हो, जिसकी निष्कलुषता पर स्वार्थ, संदेह या अहंकार की परछाई न पड़ी हो। परिवार, जो कभी सुरक्षा और संस्कार का सबसे सुदृढ़ केंद्र हुआ करते थे, आज स्वयं असंतोष, अविश्वास और विघटन की प्रयोगशाला बनते जा रहे हैं। पारिवारिक जीवन से प्रेम, सहयोग, सामंजस्य और सहनशीलता जैसे मूल तत्व तेज़ी से लुप्त हो रहे हैं। इनके स्थान पर छल, कपट, धोखाधड़ी और वैमनस्य ने जगह बना ली है। आधुनिक मनुष्य इतना आत्मकेंद्रित और लोभग्रस्त होता जा रहा है कि वह रिश्तों को तोड़ते समय न तो संकोच करता है और न ही किसी प्रकार का पश्चाताप अनुभव करता है। परिणामस्वरूप भारतीय समाज में पारिवारिक विघटन, तलाक़ और विवाह-पूर्व 'लिव-इन रिलेशनशिप' की घटनाएँ निरंतर बढ़ रही हैं। संयुक्त परिवारों का एकल परिवारों में सिमटना केवल संरचनात्मक परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह सामाजिक-मनोवैज्ञानिक असंतुलन का संकेत भी है, जिसका सीधा प्रभाव युवा पीढ़ी पर पड़ रहा है। अपराध, नशावृत्ति और अवसाद की ओर युवाओं का झुकाव इसी टूटते पारिवारिक ताने-बाने की एक गंभीर परिणति है।

मेरे दृष्टिकोण से रिश्तों का यह क्षरण पर्यावरणीय प्रदूषण से भी अधिक घातक है, क्योंकि यह समाज की आत्मा को भीतर से खोखला कर देता है। इस तथ्य की पुष्टि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट 'क्राइम इन इंडिया' (सितंबर 2025) से भी होती है। वर्ष 2023 में महिलाओं के विरुद्ध 4.48 लाख से अधिक अपराध दर्ज किए गए, जिनमें लगभग 31.4 प्रतिशत मामले पति या उसके परिजनों द्वारा की गई क्रूरता से संबंधित थे। इसी प्रकार बच्चों के विरुद्ध दर्ज 1.77 लाख अपराधों में पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत आने वाले 96 प्रतिशत से अधिक मामलों में आरोपी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि पीड़ित का परिचित या संबंधी ही था। हत्या जैसे जघन्य अपराधों में भी 'पारिवारिक कलह' एक प्रमुख कारण के रूप में उभरकर सामने आई है। ये आँकड़े केवल अपराध की नहीं, बल्कि रिश्तों के गहरे नैतिक पतन की कहानी कहते हैं।

सनातन संस्कृति में परिवार को सदैव 'संस्कारों की प्रयोगशाला' माना गया है। भारतीय परिवार व्यवस्था कभी ऐसी नैतिक शक्ति का स्रोत थी, जिसकी ओर पाश्चात्य समाज भी आकृष्ट होता था। किंतु आज वही परिवार अपनी परंपराओं, मूल्यों और सांस्कृतिक अनुशासन से दूर होता जा रहा है। युवा पीढ़ी का बढ़ता स्वकेंद्रित दृष्टिकोण इस संकट को और गहरा कर रहा है। कैरियर, भौतिक सुख-सुविधाएँ और व्यक्तिगत स्वतंत्रता उसकी प्राथमिकताओं में शीर्ष पर हैं, जबकि परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व हाशिये पर खिसकते जा रहे हैं। संभवतः यही कारण है कि पवित्र वैवाहिक बंधन के स्थान पर अस्थायी संबंधों को अधिक स्वीकार्यता मिल रही है। इस सामाजिक परिवर्तन का एक और चिंताजनक संकेत गिरती प्रजनन दर है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार शहरी भारत में कुल प्रजनन दर 1.6 तक पहुँच चुकी है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से काफी नीचे है। यह आँकड़ा भविष्य में एक ऐसे समाज की ओर संकेत करता है, जहाँ बुजुर्ग अकेलेपन से जूझेंगे और पारिवारिक सहारा एक दुर्लभ मूल्य बन जाएगा। लोकसभा की 2024 की एक रिपोर्ट बताती है कि लगभग 60 प्रतिशत भारतीय युवा 'एकाकीपन' का अनुभव कर रहे हैं, जो आगे चलकर अवसाद और नशे जैसी प्रवृत्तियों को जन्म दे सकते हैं। यूनिसेफ की विभिन्न रिपोर्टें भी यह स्पष्ट करती हैं कि किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के पीछे पारिवारिक कलह एक बड़ा कारण है।

आज परिवारों में संवादहीनता और सहनशीलता की कमी ने उस संस्कार-कवच को नष्ट कर दिया है, जो कभी संयुक्त परिवारों के रूप में समाज को संबल देता था। कोरोना काल और उससे जुड़े अनेक अध्ययनों ने यह सिद्ध किया कि संयुक्त परिवारों में रहने वाले लोगों ने भावनात्मक सहयोग के कारण कठिन परिस्थितियों का अधिक सशक्त ढंग से सामना किया। इसके विपरीत, एकल परिवारों में अकेलापन और असुरक्षा की भावना अधिक गहराई से उभरी।

यह समझना आवश्यक है कि आजीविका के कारण भौगोलिक दूरी विवशता हो सकती है, किंतु मन की दूरी केवल हमारे अहंकार और विकृत प्राथमिकताओं का परिणाम है। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा 'परिवार प्रबोधन' जैसे अभियानों के माध्यम से सामाजिक चेतना जागृत करने का प्रयास न केवल सराहनीय है, बल्कि अन्य सामाजिक संगठनों के लिए अनुकरणीय भी है। 140 करोड़ की आबादी वाले भारत में परिवार को पुनः विश्वास, संवाद और संवेदनशीलता का केंद्र बनाना केवल संस्थाओं का नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का सामूहिक दायित्व है।

ऋग्वेद की शाश्वत प्रार्थना 'संगच्छध्वं संवदध्वं' हमें साथ चलने और संवाद बनाए रखने का संदेश देती है। यदि समय रहते सांस्कृतिक और पारिवारिक चेतना को पुनर्जीवित नहीं किया गया, तो हमारी गौरवशाली परंपरा केवल आँकड़ों और इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगी। समय की माँग है कि विकास की दौड़ में हम अपनों का हाथ न छोड़ें, क्योंकि सशक्त समाज की नींव सुदृढ़ रिश्तों पर ही टिकी होती है।

लेखकः प्रो. (डॉ.) मनमोहन प्रकाश

स्वामी- स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ल द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोटः** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

संक्षिप्त खबरें

मतदाता पुनरीक्षण पर सपा सख्त, बूथ स्तर तक निगरानी के निर्देश

लालगंज (रायबरेली)। कस्बे में बुधवार को समाजवादी पार्टी की विधानसभा कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में चुनाव आयोग के विशेष प्रगाढ़ मतदाता पुनरीक्षण पर चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं को नोटिसों की सुनवाई पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष जेपी यादव ने की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा षड्यंत्रपूर्वक मतदाता बढ़ाने का प्रयास कर रही है। कहा कि सपा ऐसे मंसूबों को सफल नहीं होने देगी। उन्होंने बताया कि निगरानी के लिए 47 सेक्टर प्रभारी, 47 सेक्टर पर्यवेक्षक, 6 जोन प्रभारी और 446 बूथ प्रभारी लगाए गए हैं। आरोप लगाया कि फर्जी तरीके से फॉर्म 7 भरकर मतदाता बढ़ाए जा रहे हैं। सरकार की साजिश को विफल किया जाएगा। बैठक का संचालन विधानसभा महासचिव रमेश मौर्य ने किया। इस दौरान दिव्यांबर सिंह, सूर्यभान सिंह, अमरेंद्र यादव, बबलू बाजपेई, इरफान, धर्मेंद्र, योगेश यादव, सरदार यादव, शिव प्रकाश, नसीम, अरविंद, अमित यादव, नईम खान, सतीश महाजन, सुनील यादव, राम प्रकाश, राजकुमार यादव सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

शब-ए-बारात का त्यौहार अकीदत के साथ गया मनाया

लहरपुर, सीतापुर मंगलवार को शब-ए-बरात का त्योहार अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। मस्जिदों, खानकाहो और कब्रिस्तान में बड़ी संख्या में अकीदत मन्द रात भर जाग कर इबादत करके अल्लाह को राजी करने और दूआओं में मसरूफ रहेंगे। नगर पालिका परिषद की और से मजहबी मुक़ामात के आस पास साफ़ सफाई और पेय जल की सप्लाई सुचारू रूप से कराने की व्यवस्था की गई। शहर की मरकज मस्जिद, मदीना मस्जिद,गुरखेत बाजार जामा मस्जिद मीरा टोला जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग नमाज़ और कुरान पाक पढ़ने एवं अल्लाह की इबादत करने में व्यस्त रहे।इस के अलावा रमजान अली शाह मुरली वाले बाबा की दरगाह, अब्दुर्रहमान शाह जांबाज कलंदर, मज़ा शाह कलंदर और मुस्तफा अली शाह की दरगाह पर भी रात भर अकीदतमंदों की भीड़ देखी गई। शहर के क़ब्रिस्तानों में लोग अपने अज़ीज़ों की मजार पर अगरबत्ती जलाकर फातिहा और कुरान पाक पढ़ कर गुनाहों से निजात की दुआ की और आइंदा बुराई से दूर रहने नेक अमल करने की अल्लाह से दुआ की। महिलाओं ने अपने घरों में ही नमाज़, जिक्र,दुआ और कुरान पाक पढ़ कर इबादत की। इस मौके पर रमजान अली शाह मुरली वाले बाबा की दरगाह की भव्य सजावट की गई और भारी संख्या में लोगों ने इबादत की।

जीआरपी पुलिस ने शातिर मोबाइल चोर को पकड़ा

नैनी ,प्रयागराज। बुधवार को छिवकी रेलवे स्टेशन पर एक शातिर मोबाइल चोर इंद्रजीत सिंह को जीआरपी पुलिस ने पकड़ा। उसके कब्जे से चोरी का एक रेडमी स्मार्टफोन बरामद हुआ है।एडीजी रेलवे और एसपी रेलवे प्रयागराज के निर्देश पर इन दिनों रेलवे परिसरों में चोरी, छिनैती और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत यह गिरफ्तारी हुई।बुधवार सुबह जीआरपी थाना प्रभारी अकलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम छिवकी स्टेशन क्षेत्र में गश्त कर रही थी।जीआरपी पुलिस टीम प्लेटफार्म नंबर-1पर हावड़ा एंड की ओर पहुंची। वहां एक युवक पेड़ के नीचे संदिग्ध अवस्था में दिखा, जो पुलिस को देखते ही भागने लगा। सतर्क जवानों ने घेराबंदी कर उसे मौके पर ही पकड़ लिया।पकड़े गए आरोपी की पहचान इंद्रजीत सिंह (28 वर्ष) पुत्र निवासी देवघाट झलवा, थाना एयरपोर्ट, प्रयागराज के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके पास से रेडमी कंपनी का ग्रे कलर का टच स्क्रीन मोबाइल फोन बरामद किया गया। जांच में पता चला कि यह मोबाइल मुकदमा बीएनएस के तहत दर्ज चोरी के एक मामले से संबंधित है।पूछताछ में आरोपी इंद्रजीत ने स्वीकार किया कि वह रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों को निशाना बनाता था। खासकर सो रहे या लापरवाह यात्रियों के मोबाइल और कीमती सामान चोरी करना उसकी आदत थी। चोरी से मिले पैसों से वह अपने शौक और ऐशो-आराम पूरे करता था।

सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन लखनऊ ने 25 वर्ष से अधिक सेवा देने वाले वरिष्ठ अधिवक्ताओं को किया सम्मानित

● .....अधिवक्ता सम्मान समारोह में न्यायिक सदस्यों की गरिमामयी उपस्थिति, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के योगदान को किया गया नमन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन, लखनऊ द्वारा कार्यकारिणी सत्र 2025-26 के अंतर्गत विधि-व्यवसाय में 25 वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि पूर्ण करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ताओं के सम्मान में एक भव्य अधिवक्ता सम्मान समारोह का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, गोमती नगर स्थित सभागार में किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायिक सदस्य संतोष कुमार श्रीवास्तव एवं विशिष्ट अतिथि न्यायिक सदस्य नरेंद्र कुमार रहे, जिनका एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। समारोह के दौरान उन वरिष्ठ अधिवक्ताओं को विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जिन्होंने विधि-व्यवसाय में 25 वर्ष अथवा उससे अधिक की सेवा अवधि पूर्ण कर न्यायिक क्षेत्र में अपने अनुभव, निष्ठा एवं योगदान से समाज और बार की गरिमा को बढ़ाया है। सम्मान समारोह के उपरांत तहरी भोज (सहभोज) का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सम्मानित अधिवक्ताओं एवं उपस्थित सदस्यों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के अंतिम चरण में मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि अधिवक्ता समाज न्याय प्रणाली का एक मजबूत और महत्वपूर्ण स्तंभ है तथा वरिष्ठ अधिवक्ताओं का अनुभव युवा अधिवक्ताओं के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने ऐसे आयोजनों को बार की एकजुटता, सम्मान और परंपरा का प्रतीक बताया। कार्यक्रम का कुशल एवं प्रभावी संचालन अधिवक्ता दिलीप श्रीवास्तव द्वारा किया गया। समापन अवसर पर सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय मिश्र एवं महामंत्री शिव कुमार पाण्डेय ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, सम्मानित अधिवक्ताओं एवं कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अधिवक्ता साथियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी इस प्रकार के गरिमामय आयोजनों के निरंतर आयोजन की प्रतिबद्धता जताई।

पागल कुत्ते का आतंक, एक दर्जन लोग घायल

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के खजूर गांव, रघुनाथगंज और मीठापुर में पागल कुत्ते का आतंक फैल गया है। बुधवार को कुत्ते ने 12 लोगों को काटकर घायल कर दिया। घटना के बाद गांवों में दहशत का माहौल है। कुत्ते के हमले में खजूर गांव के वृंदावन यादव, राजेश डोम, सुनीता और बदरूनिशा घायल हुए। वहीं मीठापुर के राजेश पासवान, पन्नू यादव, भाईलाल, लोध और भीम शंकर को भी कुत्ते ने काट लिया। सभी घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि एक ही पागल कुत्ते ने अलग-अलग स्थानों पर लोगों पर हमला किया। कुत्ते ने मवेशियों को भी काटकर जख्मी किया है। इससे ग्रामीणों में भय बना हुआ है।

भारत-अमेरिका ट्रेड से पिस्ता-सेब होंगे सस्ते

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

संवाददाता सचिन बाजपेई

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच हुए नए व्यापार समझौते का सीधा असर अब आम उपभोक्ताओं की जेब पर दिखने वाला है। इस समझौते के तहत अमेरिका से आयात होने वाले पिस्ता, सेब, बादाम और अन्य ड्राई फ्रूट्स भारत में पहले से सस्ते हो सकते हैं। सरकार का दावा है कि इस डील में भारतीय किसानों और संवेदनशील कृषि क्षेत्रों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है, जिससे घरेलू उत्पादन सुरक्षित रहेगा। समझौते के अनुसार, अमेरिका से आने वाले चुनिंदा कृषि और खाद्य उत्पादों पर आयात शुल्क (टैरिफ) में कटौती की गई है। इससे अमेरिकी सेब और पिस्ता जैसे उत्पाद भारतीय बाजार में कम कीमत पर उपलब्ध हो सकेंगे। वहीं दूसरी ओर, भारत ने चावल, गेहूं, डेयरी उत्पाद और अन्य संवेदनशील कृषि वस्तुओं को इस व्यापार समझौते से बाहर रखा है, ताकि स्थानीय किसानों को नुकसान न हो। सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह व्यापार समझौता पूरी तरह पारस्परिक लाभ के सिद्धांत पर आधारित है। एक ओर भारतीय उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद सस्ते दामों पर मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में कम शुल्क और बेहतर पहुंच मिलेगी। इससे भारत के टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग और अन्य निर्यात क्षेत्रों को भी फायदा होने की उम्मीद है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार, यह समझौता भारत-अमेरिका के बीच आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करेगा। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि आयात बढ़ने की स्थिति में सरकार को घरेलू बाजार पर लगातार नजर रखनी होगी। कुल मिलाकर, यह डील उपभोक्ताओं के लिए राहत और किसानों के लिए सुरक्षा का संतुलित मॉडल मानी जा रही है।

समाजसेविका के निधन पर जताया शोक

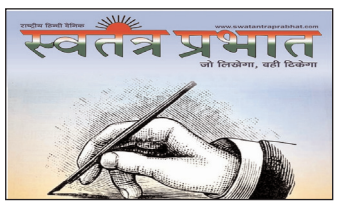

लालगंज, प्रतापगढ़। समाजसेविका के निधन पर क्षेत्रवासियों ने शोक जताया है। विकासखण्ड लक्ष्मणपुर अर्न्तगत पूरे धनई शिवबोझ गांव की समाजसेविका 76 वर्षीया राजकुमारी का बीमारी के चलते बीते मंगलवार को निधन हो गया। समाजसेविका गिरीशचंद्र मिश्र व केशव मिश्र की मां थी। निधन की जानकारी होने पर क्षेत्र के विजय पाण्डेय, रामजी जायसवाल, रामू मिश्र, रज्जन शुक्ला, ऋषि कुमार द्विवेदी, राधेश्याम मिश्र, सोनू शुक्ल, शशांक तिवारी, अनुराग उपाध्याय, आशीष द्विवेदी, दीपक शुक्ल, सत्यम सिंह, संजीव द्विवेदी, सुधांशु, संजीव पाण्डेय आदि ने गहरी संवेदना जतायी है।

बारिश में भीगी इंसानियत, चालान में उलझी व्यवस्था

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ में तेज़ बारिश के दौरान सामने आई एक घटना ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली और संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी के लोहिया पथ क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से बचने के लिए कई दोपहिया वाहन चालक सड़क किनारे शेड के नीचे खड़े हो गए थे, तभी वहां पहुंचे पुलिसकर्मियों ने उन्हें हटाने के साथ-साथ चालान काटने जैसी कार्रवाई शुरू कर दी। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही जनता में नाराज़गी फैल गई। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि बारिश से बचने के लिए मजबूर लोग पुलिस के डर से भीगते हुए अपनी बाइक लेकर आगे बढ़ने को मजबूर हुए। आम लोगों का कहना है कि यह नियमों का पालन नहीं बल्कि मानवीय संवेदना की अनदेखी है, क्योंकि लोग किसी सुविधा या उल्लंघन के इरादे से नहीं, बल्कि अचानक आई तेज बारिश से बचने के लिए रुके थे। वहीं पुलिस प्रशासन का पक्ष है कि सड़क पर वाहन खड़ा करना यातायात और सुरक्षा के लिहाज़ से खतरनाक है और उस समय वीवीआईपी मूवमेंट या सुरक्षा कारण भी हो सकते थे, साथ ही यह दावा भी किया गया कि वास्तविक चालान नहीं काटे गए। बावजूद इसके, यह घटना नियम बनाम इंसानियत की बहस को फिर से सामने ले आई है। जानकारों का मानना है कि कानून का पालन आवश्यक है, लेकिन असाधारण परिस्थितियों–जैसे तेज बारिश–में पुलिस से अपेक्षा की जाती है कि वह सख्ती के साथ-साथ मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाए। यह मामला अब सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं, बल्कि जन-पुलिस संबंधों और संवेदनशील पुलिसिंग की आवश्यकता पर बड़ा सवाल बन चुका है।

पेड़ से लटका मिला किशोर का शव इलाके में फैली सनसनी, 18 घंटे से था लापता

● आत्महत्या और हत्या के एंगल पर पुलिस कर रही जांच

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर। जनपद सीतापुर के सदरपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां घर से लापता हुए 12 वर्षीय किशोर का शव खेत में पेड़ से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मासूम की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान चाहत पुत्र हरिशंकर भार्गव उम्र करीब 12 वर्ष, निवासी देवरिया खुर्द, थाना सदरपुर के रूप में हुई है बताया जाता है कि मृतक किशोर चाहत मंगलवार शाम करीब 4 बजे घर से निकला था, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटा। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका। पूरी रात परिजन अनहोनी की आशंका में परेशान रहे। बुधवार की सुबह सदरपुर थाना क्षेत्र के टेढ़ीपुरवा गांव के पास केवानी नदी किनारे स्थित अबरार निवासी टेढ़ीपुरवा के गन्ने के खेत में पेड़ से एक किशोर का शव प्लास्टिक की पतली रस्सी के सहारे फांसी के फंदे में झूलता हुआ ग्रामीणों ने देखा शव देखकर ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सदरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ ही देर में परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए, जहां शव की पहचान चाहत के रूप में होते ही कोहराम मच गया मौके पर काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम

कार्यवाई के लिए मुख्यालय भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किए और परिजनों से पूछताछ की। प्रारंभिक तौर पर मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि किशोर द्वारा यह कदम क्यों उठाया गया, इसके कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। घटना के बाद गांव में शोक और भय का माहौल बना हुआ है!!

यूपी के अनुदेशकों के भुगतान पर सुप्रीम फैसला

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली— उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्षों से कार्यरत करीब 25 हजार अनुदेशकों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ी राहत लेकर आया है। शीर्ष अदालत ने अनुदेशकों के मानदेय को लेकर राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें केंद्र सरकार के मानकों के अनुसार 17,000 प्रतिमाह मानदेय दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी माना कि यह मानदेय वर्ष 2017 से लागू माना जाएगा, यानी अनुदेशकों को बीते वर्षों का बकाया (एरियर) भुगतान पाने का अधिकार है। यह फैसला लंबे समय से कम मानदेय पर कार्य कर रहे अनुदेशकों के संघर्ष को न्यायिक मान्यता देता है। मामले की पृष्ठभूमि में यह तथ्य सामने आया कि वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों के मानदेय को 17,000 प्रतिमाह करने का निर्णय लिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसे प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया।

इसके बाद अनुदेशकों और उनके संगठनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया, जहां उन्हें राहत मिली। राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दिए जाने पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी भी की कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में कार्य कर रहे शिक्षकों को वर्षों तक कम मानदेय पर रखना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि यह शिक्षा की गुणवत्ता पर भी असर डालता है। अदालत ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि अनुदेशकों को संशोधित मानदेय के साथ-साथ वर्ष 2017 से अब तक की बकाया राशि का भुगतान किया जाना चाहिए और राज्य सरकार को इसके लिए तय समयसीमा में प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस फैसले से न सिर्फ अनुदेशकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उनकी सेवा सुरक्षा को लेकर भी एक सकारात्मक संदेश जाएगा। शिक्षा जगत से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय संविदा और अंशकालिक शिक्षकों के अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण नजीर बनेगा और भविष्य में अन्य राज्यों में भी ऐसे मामलों पर असर डालेगा।

किसान क्रांति पदयात्राः चौथे दिन उमड़ा जनसमर्थन, समापन पर वृंदावन में होगी विशाल किसान पंचायत

● .....भाकियू (भानू) ने सरोजनीनगर प्रशासन को घेरा; स्थानीय रोजगार और शोषण के विरुद्ध आंदोलन का फूंका बिगुल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। भारतीय किसान यूनियन (भानू) के तत्वावधान में आयोजित दस दिवसीय 'किसान क्रांति पदयात्रा' के चौथे दिन पीजीआई से बंथरा तक भारी जनसमर्थन देखने को मिला, जहाँ पुष्पवर्षा और माल्यार्पण के साथ पदयात्रियों का स्वागत किया गया। प्रदेश प्रभारी ऋषि मिश्रा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सरोजनीनगर उपजिलाधिकारी से वार्ता कर भूमि विवाद, मुआवजा, बिजली और सिंचाई जैसे मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान ऋषि मिश्रा ने औद्योगिक इकाइयों और वेयरहाउसों में महिला श्रमिकों के शोषण पर कड़ी नाराजगी जताई और अशोक लेलैंड जैसी कंपनियों को एक माह के भीतर स्थानीय शिक्षित युवाओं को रोजगार देने की चेतावनी दी। एसीपी रजनीश वर्मा की मौजूदगी में शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ी इस यात्रा में बड़ी संख्या में किसान नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। यात्रा के दसवें दिन पीजीआई के वृंदावन में एक विशाल किसान पंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेश भर के किसान अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरेंगे और प्रशासन की गंभीरता न दिखाने पर बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे।

लॉटरी सिस्टम से होगा संग्रामगढ़ गांव के कोटे का चयन

लालगंज, प्रतापगढ़। विकासखण्ड रामपुर संग्रामगढ़ की ग्राम पंचायत संग्रामगढ़ में रिक्त चल रहे कोटे का चयन अब लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए पांच फरवरी से बीस फरवरी तक बंद लिफाफे में आवेदन मांगे गये हैं। आवेदन फार्म उप जिलाधिकारी कार्यालय लालगंज से प्राप्त किये जा सकते हैं। आगामी 25 फरवरी को तहसील सभागार में लॉटरी सिस्टम के द्वारा कोटे का चयन तहसील स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जाएगा। उक्त जानकारी उप जिलाधिकारी शैलेन्द्र वर्मा द्वारा जारी विज्ञप्ति में दी गयी है।

तीन सगी बहनों ने की आत्महत्या

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक ही परिवार की तीन सगी बहनों ने नौवीं मंज़िल से कूदकर आत्महत्या कर ली। यह दर्दनाक घटना शहर की भारत सिटी सोसायटी में देर रात करीब दो बजे की बताई जा रही है। मृतक बहनों की पहचान निशिका (16 वर्ष), प्राची (14 वर्ष) और पाकी (12 वर्ष) के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और परिवार गहरे सदमे में है। पुलिस के अनुसार, घटना स्थल से एक सुसाइड नोट और एक डायरी बरामद हुई है, जिसमें बहनों ने भावुक शब्दों में लिखा है– 'सॉरी पापा... हमें माफ कर दो, हम आप पर बोझ बन गए थे।' डायरी के कई पन्नों में बहनों की मानसिक स्थिति, अकेलापन और भावनात्मक तनाव का जिक्र है। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि तीनों बहनें काफी समय से मोबाइल गेमिंग और ऑनलाइन गतिविधियों में अत्यधिक रुचि ले रही थीं, जिसे लेकर पुलिस सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, तीनों बहनें पढ़ाई में ठीक थीं और ज़्यादा मेल-जोल नहीं रखती थीं। हाल के महीनों में उनके व्यवहार में बदलाव देखा गया था, लेकिन किसी को अंदेशा नहीं था कि मामला इतना गंभीर हो सकता है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, मोबाइल फोन और डायरी की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है, ताकि आत्महत्या के पीछे की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सके। इस घटना ने एक बार फिर बच्चों की मानसिक सेहत, डिजिटल दुनिया के प्रभाव और अभिभावकीय संवाद पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि समय रहते बच्चों की भावनाओं को समझना और उनसे खुलकर संवाद करना बेहद ज़रूरी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सभी तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अपहरण का आरोपी धराया, भेजा गया जेल

लालगंज, प्रतापगढ़। सांगीपुर पुलिस ने अपहरण के आरोपी को गिर तार कर जेल भेज दिया। दरोगा इन्द्रेश कुमार पुलिस बल के साथ बुधवार की सुबह गश्त पर निकले थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर अपहरण के मुकदमें में वांछित चल रहे आरोपी धीरज वर्मा पुत्र विनोद कुमार वर्मा निवासी देउम पूरब को घुइसरनाथ धाम स्थित पुल के समीप से धर दबोचा। एसओ गौरव त्रिवेदी ने बताया कि आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

सीएम करेंगे गोरक्षनाथ प्रतिमा का अनावरण अफसरों ने कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था परखी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर। जनपद सीतापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनज़र शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारियों ने शहर के शास्त्री नगर स्थित कार्यक्रम स्थल का मुआयना किया इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और अन्य आवश्यक तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया गया। मुआयना करने वालों में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर विनायक भोसले, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अनूप शुक्ला सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड स्थल और मुख्यमंत्री के आवागमन मार्गों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 फरवरी को सीतापुर के शास्त्री नगर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं इस दौरान महंत योगी तेज नाथ जी महाराज द्वारा स्थापित गुरु गोरक्ष नाथ की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री द्वारा किए जाने की संभावना है इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अधिकारियों ने हेलीपैड के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग, पार्किंग स्थल और कार्यक्रम स्थल के साथ आपातकालीन व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की।

साथ ही कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने वाले मार्गों पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की योजना बनाई जा रही है। मुआयना के दौरान अधिकारियों ने आयोजकों से भी बातचीत कर कार्यक्रम की रूपरेखा और अपेक्षित भीड़ के बारे में जानकारी ली प्रशासन का कहना है कि मुख्यमंत्री के संभावित आगमन को लेकर सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएंगी, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराया जा सके!!

नगर पंचायत की लापरवाही से भड़का आक्रोश, अध्यक्ष कार्यालय के सामने रखा गया गाय का शव

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज (रायबरेली)। नगर क्षेत्र में मृत पशुओं के निस्तारण को लेकर नगर पंचायत प्रशासन की उदासीनता एक बार फिर सामने आई है। गाय के शव के निस्तारण के लिए वाहन उपलब्ध न कराए जाने से नाराज लोगों ने बुधवार को नगर पंचायत कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने नगर पंचायत अध्यक्ष सरिता गुप्ता के कार्यालय के सामने गाय का शव रखकर जमकर नारेबाजी की। बताया गया कि नगर के घोसियाना मोहल्ले में एक गाय कई दिनों से बीमार थी, जिसकी सेवा मोहल्लेवासियों और गौ रक्षक दल के सदस्यों द्वारा की जा रही थी। मंगलवार को इलाज के दौरान गाय की मौत हो गई। इसके बाद शव के निस्तारण के लिए सभासद राघवेंद्र सूर्यवंशी के माध्यम से नगर पंचायत से संपर्क किया गया, लेकिन आरोप है कि प्रशासन ने वाहन उपलब्ध कराने से इंकार कर दिया। नगर पंचायत से मदद न मिलने पर मोहल्लेवासियों और गौ रक्षक दल के कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ गई। इसके बाद सभी लोग गाय का शव उठाकर नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे और अध्यक्ष कार्यालय के सामने रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। काफी देर तक चली बातचीत के बाद अधिकारियों के हस्तक्षेप से स्थिति को नियंत्रित किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नगर क्षेत्र में मृत पशुओं के निस्तारण की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है, जिससे आए दिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मांग की है कि नगर पंचायत भविष्य में गाय सहित अन्य मृत पशुओं के निस्तारण के लिए स्थायी समाधान सुनिश्चित करे।

कार्यालय ग्राम पंचायत भोजपुर संतरी विकासखंड गैसड़ी जनपद बलरामपुर

अल्पकालीन निविदा /आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत भोजपुर संतरी में मनरेगा योजना अंतर्गत 1- कुड़वा गाँव में मोल्लाइन के घर से छेदी चौरसिया के घर तक C.C रोड निर्माण 2.कुड़वा गाँव में राजकपूर के घर से दुःखी के घर तक C.C रोड निर्माण 3.जवाहर लाल के घर पर कूप मरम्मत कार्य के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले आरसीसी निर्माण, इत्यादि कार्यों हेतु ईट प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी ईट, बालू सीमेंट मौरंग, मिट्टी,विभिन्न साइज के सरिया ब्लाक साइन बोर्ड आदि, की आवश्यकता है सामग्री की आपूर्ति हेतु इच्छुक निविदा दाताओं से निविदा कोटेशन पंजीकृत फार्म सील बंद निविदा दिनांक 06-02-2026 से 07-02-2026 तक ग्राम पंचायत कार्यालय पर दोपहर 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाएगी जो दिनांक 08-02-2026 को गठित समिति के समक्ष निविदा खोली जाएगी उक्त सभी आपूर्ति की जाने वाले सामग्री 2025 - 2026 तक मान्य रहेगी वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग परिमंडल गोंडा द्वारा निर्धारित तारों के समक्ष की जाएगी की जाएगी शेष नियम व शर्तें किसी भी समय ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है टेंडर प्रक्रिया निरस्त हुआ स्थगित करने का पूर्ण अधिकार ग्राम पंचायत को होगी।

इम्तियाज अहमद
अध्यक्ष
ग्राम पंचायत भोजपुरी संतरी
विकास खंड गैसड़ी जनपद बलरामपुर

सचिव
नीरज कुमार
ग्राम पंचायत भोजपुर संतरी
विकासखंड गैसड़ी जनपद बलरामपुर

संक्षिप्त खबरें

शब ए बरात की रातभर इबादत में मशगूल रहे नमाज़ी अल्लाह से मांगी गुनाहों की माफी

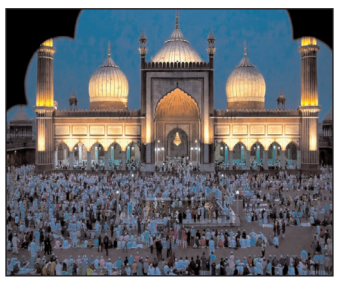

नई दिल्ली, मुस्लिम समाज ने शब ए बारात का पर्व अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस्लाम की चार सबसे मुक़द्दस पवित्र रातों में से एक मानी जाने वाली इस रात को लोगों ने सुबह तक आल्हा की इबादत और पूर्वजों की याद में बिताया। दिल्ली में मंगलवार की शाम से सड़कों पर चहल-पहल बढ गई। मस्जिदें और कब्रिस्तान रंगीन रौशनी से जगमगा गए। कब्रिस्तान में पहुंचे लोगों ने मरहूम की कब्रों पर फूल चढ़ाएं। लोगों ने अपने पूरखो की कब्रों के आसपास अगरबत्तियां जलाई कब्रिस्तान के चारों तरफ हवाओं में खुशबू समाई रही।फातिहा पढ़कर उनकी मगफिरत के लिए दुआ की। सबसे ज्यादा भीड़ जमा मस्जिद में देखी गई।ईशा की नमाज से मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद, बड़ा हिंदूराव, इंद्रलोक, रनवीर नगर, उत्तम नगर, ज़ख़ीरा, कर्म पुरा, शास्त्री पार्क, जफराबाद, सहित अन्य मस्जिदों में शुरू हुआ इबादत का सिलसिला बुधवार फज्र की नमाज तक चलता रहा। नमाजियों ने मस्जिदों में सिरातुलशबीह और नफल की नमाज के अलावा कुरान की तिलावत, तस्बीह पर जिक्रे इलाही से अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा की।

डीएम ने स्वास्थ्य उपकेंद्र का किया औचक निरीक्षण लापरवाही पर एएनएम, सीएचओ और बीसीपीएम का कटा वेतन

सीतापुर। जनपद सीतापुर में स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत परखने के लिए जिलाधिकारी राजागणपति आर ने सख्त रुख अपनाते हुए बुधवार को विकास खण्ड परसेण्डी के ग्राम गुरईपुर स्थित स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का औचक निरीक्षण किया। वीएचएसएनडी सत्र के दौरान मिली अव्यवस्थाओं पर जिलाधिकारी ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए कई अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन कटौती के निर्देश दिए, जिससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सीएचओ अर्चना से वार्ता कर सत्र संचालन, टीकाकरण और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान एएनएम अनुपमा बिना सूचना के अनुपस्थित पाई गई, जिस पर जिलाधिकारी ने 15 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। इसके साथ ही एएनएम की वैक्सीनेशन किट, ड्यूटी रजिस्टर, एचआरपी रजिस्टर और हीमोग्लोबिन मीटर की जांच की गई जिलाधिकारी ने मरीजों के रजिस्टर का अवलोकन करने के साथ दूरभाष के माध्यम से मरीजों से फीडबैक भी लिया। व्यवस्थाएं संतोषजनक न पाए जाने पर सीएचओ अर्चना के वेतन से 5 प्रतिशत कटौती तथा बीसीपीएम पूनम वर्मा का 15 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए वहीं आशा कार्यकत्री बबली एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्री राजलली देवी के समय से उपस्थित न होने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान गर्भवती महिलाओं के रजिस्टर का गहन अवलोकन किया गया। जिलाधिकारी ने सीडीपीओ से दूरभाष पर वार्ता कर अव्यवस्थाओं को लेकर कड़ी फटकार लगाई। आशा की अपडेट ड्यूटी लिस्ट की जांच के बाद जब गर्भवती महिला से लिए गए फीडबैक में अनियमितता सामने आई तो जिलाधिकारी ने आशा दीदी को कड़ी फटकार लगाते हुए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा सुरेश कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदारों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी!!

राहुल गांधी के बयान के विरोध में कांग्रेस मुख्यालय पर दिल्ली भाजपा सिख प्रकोष्ठ का जोरदार प्रदर्शन

● सैकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तार

सिख सरदार हैं, राहुल गांधी तुम गद्दार हो के नारों से गूंजा अकबर रोड स्मार्ट नेताओं ने कहा–यह पूरे सिख समाज का अपमान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली, 4 फरवरी।कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री सरदार रवनीत सिंह बिट्टू को 'गद्दार' कहे जाने के विरोध में दिल्ली भाजपा के सिख प्रकोष्ठ के नेतृत्व में आज कांग्रेस मुख्यालय, अकबर रोड के बाहर जोरदार रोष प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सचदेवा ने किया। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, विशेषकर सिख प्रकोष्ठ से जुड़े कार्यकर्ता, हाथों में तख्तियां और नारे लगाते हुए सड़कों पर उतरे।प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता लगातार 'सिख सरदार हैं, राहुल गांधी तुम गद्दार हो' जैसे नारे लगा रहे थे। उनका कहना था कि राहुल गांधी का बयान केवल एक मंत्री के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह पूरे सिख समाज और उसकी गौरवशाली परंपरा पर सीधा हमला है। प्रदर्शनकारी पहले मानसिंह रोड पर एकत्र हुए, जहां उन्हें प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सचदेवा, सांसद श्री योगेन्द्र चांदोलिया, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आर.पी. सिंह, विधायक सरदार तरविंद्र सिंह मारवाह, प्रदेश मंत्री सरदार इमप्रीत सिंह बख्शी तथा सिख प्रकोष्ठ संयोजक सरदार चरणजीत सिंह लवली सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। इसके बाद सभी नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय की ओर बढ़े। रास्ते में दो पुलिस बैरिकेड्स पार करने के बाद तीसरे बैरिकेड पर भारी पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को रोक लिया और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर बसों में भरकर संसद मार्ग थाने ले जाया गया, जहां से कुछ समय बाद चेतावनी देकर उन्हें छोड़ दिया गया।प्रदर्शन को संबोधित करते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि राहुल गांधी का बयान कोई सामान्य राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि यह कांग्रेस और गांधी परिवार की सिख समाज के प्रति मानसिकता को उजागर करता है। उन्होंने कहा, '1984 में भी कांग्रेस ने सिखों को गद्दार समझा था और आज भी वही सोच सामने आ रही है। आज राहुल गांधी के मुंह से उनके मन के भाव बाहर आ गए हैं सचदेवा ने आगे कहा कि सिख कौम देश के लिए हमेशा बलिदान देती आई है। गुरु श्री गोबिंद सिंह जी की राष्ट्रभक्त परंपरा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी वीर कौम के सिपाही को गद्दार कहना पूरे देश को शर्मसार करने जैसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी आज तक 1984 की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाई है।भाजपा विधायक सरदार तरविंद्र सिंह मारवाह ने कहा कि राहुल गांधी ने केवल एक मंत्री को नहीं, बल्कि देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले पूरे सिख समाज को अपमानित किया है। उन्होंने कांग्रेस पर 1984 के सिख विरोधी दंगों की याद दिलाते हुए कहा कि आज भी पार्टी की सोच वही है।भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आर.पी. सिंह ने राहुल गांधी के बयान को संसद की गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि एक निर्वाचित सांसद, विशेषकर एक सिख नेता, को गद्दार कहना सभ्यता और मर्यादा की सभी सीमाएं पार करने जैसा है। उन्होंने मांग की कि राहुल गांधी को इस बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। सिख प्रकोष्ठ के संयोजक सरदार चरणजीत सिंह लवली ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी का इतिहास सिख समाज के प्रति हमेशा अपमानजनक रहा है। चाहे 1984 का सिख दंगा हो या अन्य धार्मिक मुद्दे, कांग्रेस ने हमेशा सिख समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते, तब तक भाजपा का यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इस प्रदर्शन में प्रदेश पदाधिकारी श्री विष्णु मित्तल प्रवीण शंकर कपूर बृजेश राय संतोष ओझा विनोद सहरावत, सरदार ओंकार सिंह थापड़, सरदार कुलदीप सिंह, निगम पार्षद सरदार अर्जुन सिंह मारवाह, सरदार कुलविंदर सिंह बंटी अमित गुप्ता, सरदार जसमीन सिंह नोनी, सरदार रविन्द्र सोनू, सरदारनी कुलजीत कौर, सरदारनी प्रीति सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।भाजपा नेताओं ने साफ कहा कि सिख समाज के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और इस मुद्दे पर कांग्रेस को जवाब देना ही होगा।

दलित युवक को दो लोगों ने घर में घुसकर पीटा

दोनों आरोपियों पर पुलिस ने दर्ज किया दलित उत्पीड़न का मुकदमा

लंभुआ। सुल्तानपुर दलित युवक को जाति सूचक शब्दों की गालियां देते हुए घर में घुसकर मारना गांव के ही दो लोगों के लिए महंगा साबित हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के समहुता खुर्द निवासी दलित अमन गौतम द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक गांव के ही पवन सिंह तथा विक्रम सिंह द्वारा माताजी के मरने के बाद पचास हजार दिए थे। अब पैसे की वापसी मांगने पर दोनों आरोपी जाति सूचक शब्दों की गालियां देते हुए मारने पीटने लगे। जान बचाकर घर के अंदर भगाने के बाद दोनों घर में घुसकर मारे पीटे। पुलिस के पहुंचने के बाद किसी तरह जान बची। पीड़ित दलित युवक की तहरीर पर कोतवाली लंभुआ में दोनों आरोपियों पर दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज हुआ। कोतवाली प्रभारी धीरज कुमार ने बताया कि पुलिस जांच कर रही है।

बंदी के फरार होने का मामला सुरक्षा में तैनात आरक्षी निलंबित, चार टीमें तलाश में लगी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर। जनपद सीतापुर में न्यायालय अभिरक्षा से फरार हुए विचाराधीन बंदी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पॉक्सो कोर्ट में पेशी के दौरान बंदी की सुरक्षा में तैनात मुख्य आरक्षी राजकुमार मिश्रा को पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही नगर कोतवाली क्षेत्र में संबंधित आरक्षी के खिलाफ लापरवाही बरतने के आरोप में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मामला मंगलवार दोपहर का है, जब जिला जेल से न्यायालय में पेशी के लिए लाया गया विचाराधीन बंदी रोहित मारुति पुत्र स्वर्गीय रामू निवासी मछली मंडी, कोतवाली नगर क्षेत्र, पॉक्सो कोर्ट में पेशी के बाद वापस ले जाया जा रहा था इसी दौरान वह न्यायालय अभिरक्षा से चकमा देकर फरार हो गया बंदी के फरार होते ही कोर्ट परिसर और आसपास अफरा-तफरी मच गई फरार बंदी रोहित मारुति को 21 जनवरी 2026 को नाबालिग लड़की को भगाने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी पर चोरी के कई पुराने मुकदमे भी दर्ज हैं, जिससे उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि सामने आती है। घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू की गई प्रारंभिक जांच में सुरक्षा में गंभीर लापरवाही सामने आने पर बंदी की निगरानी में तैनात मुख्य आरक्षी राजकुमार मिश्रा को निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया फरार बंदी की तलाश के लिए स्वाट टीम सहित चार विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया है। नगर कोतवाली समेत कई थानों की पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है जिले की सीमाओं पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही फरार बंदी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा इस घटना ने एक बार फिर न्यायालय पेशी के दौरान बंदियों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं!!

क्लोन ऐप से करोड़ों की ठगी, बड़ा नेटवर्क का खुलासा

● **साइबर क्राइम व स्हल ने असम-मुंबई से 7 आरोपियों को पकड़ा**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

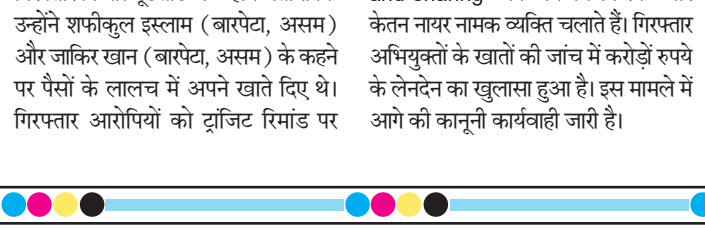

सुल्तानपुर – साइबर क्राइम और एसओजी ने एक बड़े ऑनलाइन ट्रेडिंग धोखाधड़ी का भंडाफोड़ करते हुए असम और मुंबई से सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने एक कंपनी का क्लोन ऐप बनाकर शेयर बाजार में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी की थी। पुलिस ने विभिन्न पीड़ितों से कुल 2 करोड़ 75 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का खुलासा किया है। इस मामले की शुरुआत शफीपुर निवासी भास्कर पांडेय की शिकायत से हुई। उन्होंने फेसबुक पर शेयर बाजार में मुनाफा देने वाली एक कंपनी का विज्ञापन देखा था। ऑनलाइन ट्रेडिंग की जानकारी के लिए उन्होंने अपनी डिटेल्स भरीं। कुछ दिनों बाद उन्हें श्रुति असाती नाम की एक महिला का व्हाट्सएप कॉल आया, जिसने उन्हें ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए प्रेरित किया और एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया। ग्रुप के टीचर/प्रोप्राइटर दौलत जैन ने व्हाट्सएप मैसेज के जरिए एक स्कीम बताई, जिसमें कम समय में शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाकर भारी मुनाफा कमाने का लालच दिया गया। विश्वास में लेकर भास्कर पांडेय से पहले कुछ पैसा लगवाया गया और उन्हें शुरुआती मुनाफा भी दिखाया गया। बाद में उनसे कुल 10,11,689.75 रुपये और लगवा लिए गए, जो उन्हें कभी वापस नहीं मिले। जांच में पता चला कि यह धोखाधड़ी मूल कंपनी का क्लोन ऐप बनाकर की गई थी। भास्कर पांडेय की शिकायत पर थाना साइबर क्राइम में मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान पता चला कि इसी गिरोह ने अमेठी के अभिषेक सिंह से लगभग 85 लाख रुपये और लखनऊ के अपनीश सिंह से लगभग 1 करोड़ 85 लाख रुपये की ठगी की थी। इन मामलों में भी संबंधित साइबर क्राइम थानों में केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित टीम ने जांच शुरू की। भास्कर पांडेय के खाते से ट्रांसफर किए गए पैसे की केवाईसी से पता चला कि यह राशि हनीफ एग्रो ट्रेडर्स (प्रोप्राइटर हनीफ काजी, कामरूप, असम) और शमशुद्दीन अहमद (कामरूप, असम) के खातों में गई थी। साइबर टीम ने असम जाकर हनीफ काजी और शमशुद्दीन अहमद को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि उन्होंने शफीकुल इस्लाम (बारपेटा, असम) और जाकिर खान (बारपेटा, असम) के कहने पर पैसों के लालच में अपने खाते दिए थे। गिरफ्तार आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर सुल्तानपुर लाया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक टीम मुंबई भेजी गई थी। विश्लेषण और मुखबिरों की सूचना के आधार पर टीम ने मुंबई से तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान संतोष सुर्वे (निवासी भिवंडी, मुंबई), विजय ईश्वर कलान्तरे (निवासी नवी मुंबई, महाराष्ट्र) और फरीद मलिक (निवासी मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल) के रूप में हुई है। इन्हें पूछताछ के लिए सुल्तानपुर लाया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे 'SHIKA Growing and sharing' नामक कंपनी के लिए बैंक खाते, चेकबुक, एटीएम और सिम कार्ड एकत्र कर उपलब्ध कराते थे। उन्होंने बताया कि यह असली कंपनी नहीं है, बल्कि उसका क्लोन बनाकर लोगों से धोखाधड़ी की जाती थी। आरोपियों को इस काम के लिए कमीशन मिलता था। आरोपियों ने यह भी बताया कि 'ASHIKA Growing and sharing' को धनंजय फिस्के और केतन नायर नामक व्यक्ति चलाते हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के खातों की जांच में करोड़ों रुपये के लेनदेन का खुलासा हुआ है। इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है।

आगामी त्योहार महाशिवरात्रि को लेकर सुरियावा कोतवाली परिसर में पीस कमेटी बैठक का आयोजन

भदोही /सुरियावां 4 फरवरी 2026 बुधवार को उच्च अधिकारियों के निर्देशन में सुरियावा कोतवाली परिसर में थाना अध्यक्ष मनीष द्विवेदी के द्वारा आगामी पर्व महाशिवरात्रि को लेकर बैठक किया गया जिसमें क्षेत्र संभ्रांत व्यक्तियों एवं धर्मगुरु व आयोजक संग बैठक कर समस्याओं के बारे में जानकारी लिया ताकि समय से पहले समस्याओं का समाधान किया जा सके इस मौके पर उन्होंने बताया कि शासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करना सुनिश्चित तरीके से करना अनिवार्य है इस मौके पर आयोजकयो से शिव बारात व निकलने वाली झांकियां के बारे में विस्तृत जानकारी लिया लिया तथा बताया कि पर्व को शांति एवं सौहार्दपूर्ण सौहार्दपूर्ण रूप से मनाये किसी भी प्रकार की शर्त को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा सुरक्षा की दृष्टि से हर मंदिर एवं शिवालयों में महिला एवं पुरुष फोर्स की ड्यूटी लगाई गई है इस मौके पर चौकी इंचार्ज अभिया चौकी इंचार्ज पाली अवधेश कुमार उमर उमर अनिल सिंह राकेश वर्मा राजा बाबू कैलाश सरोज जयशंकर उर्फ नानक सुरेंद्र विश्वकर्मा उमाशंकर अश्वनी साहू सहित काफी संख्या में लोग लोग मौजूद रहे।

योग दर्शन और नेतृत्व विकास कोर्स का सफल आयोजन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता
प्रदीप यादव

दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह ईवनिंग कॉलेज ने विवेकानंद केंद्र दिल्ली के सहयोग से आयोजित 45-घंटे के लीडरशिप डेवलपमेंट सर्टिफिकेट कोर्स के अंतर्गत योग एवं दर्शन मॉड्यूल को सफलतापूर्वक संपन्न किया इस कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय के सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट एवं प्रक्रम-द स्पोर्ट्स सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में किया गया कॉलेज के प्राचार्य प्रो अरुण अत्री ने अपने उद्बोधन में विवेकानंद केंद्र के प्रयासों की सराहना करते हुए इसके योगदान की विशेष प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि केंद्र के मार्गदर्शन से छात्रों को अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं को पहचानने और विकसित करने का महत्वपूर्ण अवसर मिला।

साथ ही उन्होंने आयोजकों एवं प्रतिभागियों को इस प्रकार के प्रयासों को निरंतर जारी रखने हेतु पूर्ण समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान किया। विवेकानंद केंद्र, दिल्ली के उपप्रमुख डॉ. निखिल यादव ने अपने वक्तव्य में छात्रों को एक महान विचार का स्वप्न देखने उसी को जीने तथा अपने संपूर्ण व्यक्तित्व में उसे आत्मसात करने का आह्वान किया। उन्होंने सशक्त चरित्र निर्माण के लिए ईमानदारी और जवाबदेही के महत्व पर भी विशेष बल दिया कार्यक्रम के समन्वयक प्रोफेसर अमित सोनी ने योग को केवल आसन और प्राणायाम तक सीमित न मानते हुए उसके व्यापक दार्शनिक अर्थ को स्पष्ट किया तथा छात्र के सर्वांगीण विकास में योग की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। कार्यक्रम के समापन दिवस पर लगभग 60 छात्रों एवं प्राध्यापकों द्वारा सामूहिक रूप से 108 सूर्य नमस्कारों के महायज्ञ का आयोजन किया गया। अनुशासन, समर्पण और उत्साह के साथ किए गए इस अभ्यास ने नेतृत्व, टीमवर्क और योगिक मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति प्रस्तुत की। यह आयोजन योग दर्शन और राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित समेकित शिक्षा के सकारात्मक प्रभाव को उजागर करता है दिल्ली विश्वविद्यालय के अनोखी पहल से छात्र उत्साहित हुए।

दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में आयोजित हुआ भव्य हिंदू सम्मेलन, शामिल हुए हजारों सनातनी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता
स्वतंत्र सिंह भुल्लर

दिल्ली में इन दिनों हिंदू समाज को संगठित करने, सांस्कृतिक चेतना जागृत करने और राष्ट्रहित से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श हेतु 2000 से अधिक हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 1 फरवरी 2026 को ग्रेटर कैलाश पार्ट-2 स्थित सनातन धर्म मंदिर में एक भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों ने सहभागिता की। इस कार्यक्रम का आयोजन ग्रेटर कैलाश क्षेत्र और अलकनंदा अपार्टमेंट्स के स्थानीय नागरिकों द्वारा किया गया।इस सम्मेलन का मूल उद्देश्य यह संदेश देना था कि हिंदू समाज ही समाज में सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है, और इसके लिए 'पंच परिवर्तन' को व्यवहार में उतारना समय की आवश्यकता है। कार्यक्रम के सचिव पुष्कर सिन्हा ने अपने विचार रखते हुए कहा कि पंच परिवर्तन केवल एक विचारधारा नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के पुनर्निर्माण का व्यावहारिक मार्ग है, जिसे प्रत्येक हिंदू को अपने दैनिक जीवन में अपनाना होगा। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 10:30 बजे शिव पंचाक्षर स्तोत्र से हुई। इसके पश्चात सद्गुरु डॉ. चारुदत्त पिंगळे ने हिंदुत्व विषय पर प्रेरक उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व जीवन जीने की एक समग्र पद्धति है और हमें अपनी ज्ञान परंपरा को समझते हुए झूठे नैरेटिव से बाहर निकलना होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि 'जो जीता वही सिकंदर' जैसे वाक्य भारतीय इतिहास और चेतना के विपरीत हैं, क्योंकि भारत में विजेता चंद्रगुप्त मौर्य थे, न कि सिकंदर। इसी प्रकार कुछ प्रचलित कहावतों और धारणाओं पर पुनर्विचार करने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि हमें अपने शब्दों और विचारों को भारतीय संस्कृति और राष्ट्रहित के अनुरूप ढालना होगा। इसके बाद ताल वाद्य समुच्चय (परकशन एन्सेम्बल) तथा कलारीपयट्टू जैसे शारीरिक एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनों ने विशेष रूप से युवाओं का उत्साह बढ़ाया।

बड़ी संख्या में युवाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम, योग प्रदर्शन और मार्शल आर्ट प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। पर्यावरण संरक्षण विषय पर आयोजित इंटरैक्टिव सत्र में श्री पीपल बाबा, अश्वनी खुराना एवं डॉ. राज मिश्रा ने अपने विचार रखे। इस सत्र का संचालन पुष्कर सिन्हा द्वारा किया गया। वक्ताओं ने पर्यावरण को बचाने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक दायित्वों पर बल दिया और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीने का संदेश दिया।कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर क्षेत्र सह सेवा प्रमुख मिथलेश मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि संघ ने स्थापना काल से ही सेवा कार्यों को प्राथमिकता दी है। कोरोना काल में करोड़ों स्वयंसेवकों द्वारा किया गया सेवा कार्य हिंदू समाज की एकता और संवेदनशीलता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण, महाकुंभ में 65 करोड़ हिंदुओं की सहभागिता और विभिन्न सेवा अभियानों से यह सिद्ध होता है कि यदि हिंदू समाज संगठित होकर कार्य करे तो भारत की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे भटकाने वाले तत्वों से सावधान रहें और पंच परिवर्तन के विषयों को अपने जीवन में आत्मसात करें। कार्यक्रम में कुटुंब प्रबोधन, संघ के 100 वर्ष, तथा पंच परिवर्तन पर आधारित कथक, भरतनाट्यम, लोक नृत्य, मोहिनीअट्टम और योग प्रदर्शनों ने दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया।इस अवसर पर गुरुदेव श्री अनीश, डॉ. गिरधर प्रसाद भगत, संजीव जी दक्षिणी विभाग कार्यवाह अजय उपाध्याय जिला कार्यवाह, कालकाजी सहित संघ के अनेक पदाधिकारी एवं समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे।कार्यक्रम की आयोजन समिति में अध्यक्ष रजनीश गोयनका, सचिव पुष्कर सिन्हा, कोषाध्यक्ष डॉ. हमेंद्र मित्तल, पूजा तिवारी सहित अन्य कार्यकर्ता सक्रिय रूप से सम्मिलित रहे। कार्यक्रम का संपूर्ण संचालन विवेक दीक्षित द्वारा किया गया। सम्मेलन का समापन प्रसाद (भंडारा) के साथ हुआ और सभी सहभागियों ने यह संकल्प लिया कि वे पंच परिवर्तन को अपने जीवन में अपनाकर समाज और राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

बृजमोहन लाल शकुंतला देवी इंटर कॉलेज में वार्षिकोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ सपन्न

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बिसवाँ (सीतापुर) बृजमोहन लाल शकुन्तला देवी इंटर कॉलेज, मझिगवाँ (पोस्ट-बन्नी-खरैला), बिसवाँ में वार्षिकोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह भव्य एवं गरिमामय वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह समारोह शैक्षिक गरिमा, सांस्कृतिक चेतना और प्रेरणादायी मूल्यों से परिपूर्ण रहा, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों की अंतर्निहित प्रतिभाओं का सम्मान कर उनके सर्वांगीण विकास को सुदृढ़ करना था। समारोह की अध्यक्षता एन.के.के.सी. पी.जी. कॉलेज, टिकरा बिसवाँ के निदेशक श्री संतोष कुमार वर्मा ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिसवाँ विधायक मा0 निर्मल वर्मा रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री गांधी पी.जी. कॉलेज, सिधौली के समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ. अजय कुमार वर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। अतिथियों ने अपने संबोधन में शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम बताते हुए विद्यार्थियों को अनुशासन, परिश्रम और नैतिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ने का प्रेरक संदेश दिया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार द्वारा विद्यार्थियों की शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं सह-शैक्षिक उपलब्धियों का विधिवत सम्मान किया गया। पूर्व में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र-छात्राओं को अतिथियों द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं मेडल प्रदान किए गए, जिससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, प्रतिस्पर्धात्मक भावना एवं नेतृत्व क्षमता का विकास हुआ। समारोह में नन्द किशोर कैलाश चन्द्र महाविद्यालय, टिकरा के ओ.एस.डी. डॉ. राहुल वर्मा, चीफ प्रॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह, राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी डॉ. शिवांशु राठौर, ओमप्रकाश, अंकित वर्मा, मनीष वर्मा, महक शुक्ला, कोमल वर्मा, प्रदीप वर्मा, विशेश्वर दयाल डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉ. प्रीतम सिंह एवं शिक्षक बिजनेश कुमार, सुरेन्द्र वर्मा, रवीकान्त वर्मा, तथा जनता इंटर कॉलेज, कल्याणपुर के प्रधानाचार्य मो. इदरीश एवं शिक्षक अर्जुन वर्मा, अमित वर्मा, दलबीर सिंह, प्रमोद चौरसिया, सतनाम यादव, अजय वर्मा एवं राकेश कुमार की उल्लेखनीय सहभागिता रही। वहीं एस.जे.डी. इंटर कॉलेज, बिसवां के प्रवक्ता मकसूद मली, आदर्श बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, टिकरा के रसायन प्रवक्ता मो. शुएब, बृजेंद्र बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रवक्ता शोभित वर्मा, तथा बी.एल.एस.डी. इंटर कॉलेज, मझिगवाँ के प्रधानाचार्य दिवाकर वर्मा एवं उपप्रधानाचार्य सतीश चन्द्र वर्मा भी समारोह में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समन्वयन एवं संचालन कमलेश भार्गव द्वारा कुशलतापूर्वक किया गया। साथ ही जितेन्द्र कुमार, पुष्पेन्द्र वर्मा, सुमन वर्मा, विकास निगम, विवेक अवस्थी एवं लवकुश वर्मा की भी गरिमामयी उपस्थिति रही।

समारोह में विद्यालय के अध्यक्ष धुनरिया, उपाध्यक्ष चन्द्रमोहन वर्मा तथा प्रबंधक एवं संस्थापक डॉ. सुधाकर वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। डॉ. सुधाकर वर्मा (जन्तु विज्ञान विभाग, शिया पी.जी. कॉलेज एवं असिस्टेंट डीन, सी.डी.सी., लखनऊ विश्वविद्यालय) ने अतिथियों, शिक्षाविदों, अभिभावकों एवं क्षेत्रीय नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण और समाज के उज्ज्वल भविष्य की सुदृढ़ आधारशिला होते हैं। समग्र रूप से यह समारोह अनुशासन, प्रेरणा और शैक्षिक उत्कृष्टता का सशक्त संदेश देते हुए अत्यंत सफल एवं सराहनीय ढंग से संपन्न हुआ, जिसे उपस्थित ज